

# **GUPTA**

---

# **CLASSES**

## **Current Affairs**

**August 2024**

**Hindi**

**Part-1**



**GUPTA**

---

**CLASSES**

# Current Affairs Q&A PDF – August 2024

## Table of Contents

NATIONAL AFFAIRS .....	5
INTERNATIONAL AFFAIRS .....	29
GOVT SCHEMES .....	32
VISITS .....	39
BANKING AND FINANCE .....	43
ECONOMY AND BUSINESS .....	84
MoU's AND AGREEMENTS .....	89
APPOINTMENTS AND RESIGNATIONS .....	104
AWARDS AND RECOGNITIONS .....	115
SUMMITS, CONFERENCES .....	123
COMMITTEE AND MEETING .....	126
INDEX .....	128
ACQUISITION AND MERGERS .....	134
DEFENCE .....	136
SCIENCE AND TECHNOLOGY .....	142
SPORTS .....	149
BOOKS AND AUTHORS .....	154
OBITUARY .....	157
IMPORTANT DAYS .....	163
ENVIRONMENT .....	179
APP and WEB PORTAL .....	180
CURRENT STATIC BANKING .....	187
CA STATIC GK .....	212

## NATIONAL AFFAIRS

1. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने \_\_\_\_\_ को पृथ्वी भवन, नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया।

- 1) 5 जून 2024
- 2) 1 मई 2024
- 3) 27 जुलाई 2024
- 4) 19 अप्रैल 2024
- 5) 25 मार्च 2024

उत्तर- 3) 27 जुलाई 2024

### स्पष्टीकरण:

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने 27 जुलाई, 2024 को पृथ्वी भवन, नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया, जो सभी पृथ्वी प्रणाली विज्ञानों जैसे: वायु (वायुमंडल), जल (जलमंडल), भूमि (स्थलमंडल), ठोस पृथ्वी (हिममंडल), जीवन (जीवमंडल) और उनकी अंतःक्रियाओं में MoES द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लगभग 20 वर्षों को चिह्नित करता है, जो वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- महासागर विकास विभाग (DOD) जुलाई 1981 में भारत के प्रधानमंत्री (PM) के सीधे प्रभार के तहत मंत्रिमंडल सचिवालय के एक हिस्से के रूप में बनाया गया था। यह मार्च 1982 में एक अलग विभाग के रूप में अस्तित्व में आया।
- फरवरी 2006 में, भारत सरकार ने DOD को महासागर विकास मंत्रालय के रूप में अधिसूचित किया।
- जुलाई 2006 में, महासागर विकास मंत्रालय को राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
- MoES ने अपने 18वें स्थापना दिवस के अवसर पर जनोपयोगी और लाभकारी 4 महत्वपूर्ण प्रकाशनों का शुभारंभ किया।

### विकल्प संशोधन:

1. जून 2024 में कवर किया गया: 5 जून 2024

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत एक स्वायत्त सोसायटी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) ने 5 जून 2024 को नई दिल्ली, दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया।

2. मई 2024 में कवर किया गया: 1 मई 2024

1 मई, 2024 को, दिल्ली में आर्मी डेंटल सेंटर ऑफ रिसर्च एंड रेफरल (ADC R&R), एक विशेषज्ञ दंत चिकित्सा केंद्र, जिसकी स्थापना 1 मई, 1999 को हुई थी, ने अपनी 25वीं वर्षगांठ (रजत जयंती) मनाई। इस कार्यक्रम के दौरान, पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ (GoC-in-C) लैफिटनेंट जनरल MK कटियार द्वारा सेना डाक सेवा द्वारा एक विशेष डाक कवर का अनावरण किया गया।

3. अप्रैल 2024 में कवर किया गया: 19 अप्रैल 2024

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), भारत में बीमा कंपनियों और बिचौलियों का वैधानिक निकाय, 19 अप्रैल 2024 को अपनी रजत जयंती (25 वर्ष) मनाएगा। IRDAI का गठन IRDAI अधिनियम, 1999 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था और इसे 19 अप्रैल 2000 को शामिल किया गया था।

### Dear Aspirants,

We have introduced a new explanation section called "Option Revision" Exclusively on our Daily CA App Quiz. It will help aspirants to revise last 4 months CA via options. The news theme, relevant topic, and importance are taken into consideration when choosing an option.

Question No. 1 gives you preview about option revision., Aspirants can get option revision for rest of questions on our Daily CA App Quiz(Explanation part)

We would like to notify you that all kind of Question & Answer (Q&A) PDF for paid subscribers will be discontinued from December 31 2024.  
Subscribers can attend the Quiz as Usual!!!

2. विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में (जुलाई'24 में) REC लिमिटेड के 55वें स्थापना दिवस पर \_\_\_\_\_ में नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम (NFMS) नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है।

- 1)बेंगलुरु, कर्नाटक
- 2)गुरुग्राम, हरियाणा
- 3)पुणे, महाराष्ट्र
- 4)झाकरी, हिमाचल प्रदेश
- 5)मुंबई, महाराष्ट्र

उत्तर- 2)गुरुग्राम, हरियाणा

**स्पष्टीकरण:**

25 जुलाई 2024 को, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, विद्युत मंत्रालय (MoP) और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने गुरुग्राम, हरियाणा में REC लिमिटेड के 55वें स्थापना दिवस पर नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम (NFMS) नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया।

i.NFMS MoP की एक प्रमुख पहल है, जो पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख फीडरों (11 किलोवोल्ट (KV) आउटगोइंग) की बिजली आपूर्ति के घंटों, कटौती और समग्र स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी तक वास्तविक समय में पहुँच प्रदान करती है।

ii.यह हितधारकों को सूचित और कार्रवाई योग्य निर्णय लेने, वितरण कंपनियों (DISCOMS) में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने और अंततः अंतिम उपयोगकर्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ाने की अनुमति देगा।

3. जुलाई 2024 में, उत्तर प्रदेश (UP) के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए \_\_\_\_\_ का अनुपूरक बजट पेश किया।

- 1)16,582.45 करोड़ रुपये
- 2)14,264.68 करोड़ रुपये
- 3)11,481.27 करोड़ रुपये
- 4)12,909.93 करोड़ रुपये
- 5)17,694.35 करोड़ रुपये

उत्तर- 4)12,909.93 करोड़ रुपये

**स्पष्टीकरण:**

30 जुलाई, 2024 को उत्तर प्रदेश (UP) के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए 12,909.93 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया, जो [फरवरी 2024](#) में पेश किए गए मूल बजट (7.36 लाख करोड़ रुपये) का 1.66% है।

- उद्देश्य: औद्योगिक विकास, ऊर्जा और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा देना।
- अनुपूरक बजट में राजस्व खाते पर 4,227.94 करोड़ रुपये और पूँजी खाते पर 7,981.99 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है।

- औद्योगिक क्षेत्र में विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार को बढ़ावा देने के लिए 7,500.18 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- राज्य के ऊर्जा संसाधनों और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए ऊर्जा विभाग के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया।

**4. जुलाई 2024 में, कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर \_\_\_\_\_ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।**

- 1)बैंगलुरु उत्तर जिला
  - 2)बैंगलुरु पश्चिम जिला
  - 3)बैंगलुरु पूर्व जिला
  - 4)बैंगलुरु मध्य जिला
  - 5)बैंगलुरु दक्षिण जिला
- उत्तर- 5)बैंगलुरु दक्षिण जिला

**स्पष्टीकरण:**

26 जुलाई 2024 को, कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर 'बैंगलुरु दक्षिण जिला' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नाम बदलने का प्रस्ताव 'ब्रांड बैंगलुरु' के साथ जुड़ने की स्थानीय मांग के जवाब में किया गया था।

i.जिले में रामनगर, मगदी, कनकपुरा, चत्रपटना और हरोहल्ली तालुका शामिल हैं।

ii.बैंगलुरु से 50 किलोमीटर (km) दूर रामनगर शहर, जिला मुख्यालय के रूप में काम करना जारी रखेगा।

**5. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य M. सिंधिया ने हाल ही में (अगस्त'24 में) नई दिल्ली, दिल्ली में में नेटवर्क संचालन केंद्र (NOC) का उद्घाटन किया।**

- 1)सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC)
- 2)नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (NIC)
- 3)सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (C-DOT)
- 4)नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC)
- 5)भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)

उत्तर- 3)सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (C-DOT)

**स्पष्टीकरण:**

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य M. सिंधिया, संचार मंत्रालय (MoC) और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) ने केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS) डॉ. पेम्मासनी चंद्र शेखर, MoC और ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) के साथ मिलकर नई दिल्ली, दिल्ली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (**C-DOT**) में नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (NOC) का उद्घाटन किया।

- NOC भारत में टेलिकॉम नेटवर्क में साइबर खतरों की पहचान करने और उन पर नज़र रखने के उद्देश्य से स्वदेशी रूप से विकसित सुरक्षा बुनियादी ढांचे की मेजबानी करता है।
- M सिंधिया ने भारत संचार निगम लिमिटेड (**BSNL**) लाइव नेटवर्क पर एक पायलट **5G** (पांचवीं पीढ़ी की तकनीक) कॉल भी की, जहां यह 5G कॉल स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए 5G रेडियो और 5G कोर नॉन-स्टैंड अलोन (NSA) का उपयोग करके की गई थी।

**6. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने \_\_\_\_\_ से स्टैंडर्ड्स ऑफ कालिटी ऑफ सर्विस ऑफ एक्सेस एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज जारी किए हैं।**

- 1) जनवरी 2025
- 2) अक्टूबर 2024
- 3) दिसंबर 2024
- 4) नवंबर 2024
- 5) अप्रैल 2025

## उत्तर- 2) 1 अक्टूबर 2024

### स्पष्टीकरण:

2 अगस्त 2024 को, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने संशोधित रेगुलेशन जारी किए, जिसका नाम, '**द स्टैंडर्ड ऑफ क्लालिटी ऑफ सर्विस ऑफ एक्सेस (वायरलाइन्स एंड वायरलेस) सर्विस रेगुलेशंस 2024 (06 ऑफ 2024)**' है। ये संशोधित रेगुलेशन एक्सेस (फिक्स्ड और मोबाइल) और ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए लागू हैं।

- ये रेगुलेशन **1 अक्टूबर 2024** से लागू होंगे।
- इसने सर्विस प्रोवाइडर्स को अपनी वेबसाइट पर प्रौद्योगिकी (**2G/3G/4G/5G**) के अनुसार मोबाइल कवरेज मानचित्र प्रदर्शित करने का आदेश दिया है, ताकि उपयोगकर्ता या उपभोक्ता सूचित निर्णय ले सकें।
- TRAI ने कुछ मापदंडों जैसे: नेटवर्क उपलब्धता, कॉल डॉप, अपलिंक और डाउनलिंक में वॉयस पैकेट डॉप दर, सेल स्तर पर अन्य के आधार पर प्रदर्शन एकत्र करने का निर्णय लिया है। [अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें](#)

7. अगस्त 2024 में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) ने पूरे भारत में \_\_\_\_\_ के लिए 936 किलोमीटर (km) की लंबाई के साथ 8 नेशनल हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी।

- 1) 19,744 करोड़ रुपये
- 2) 86,000 करोड़ रुपये
- 3) 50,655 करोड़ रुपये
- 4) 70,163 करोड़ रुपये
- 5) 32,000 करोड़ रुपये

उत्तर- 3) 50,655 करोड़ रुपये

### स्पष्टीकरण:

प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) ने पूरे भारत में **50,655 करोड़ रुपये** की लागत से **936** किलोमीटर (km) की लंबाई वाली **8** नेशनल हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंकिंग कानूनों में कई महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है, जिसमें प्रति जमा खाते में नामांकित व्यक्तियों की संख्या **4** तक बढ़ाना और संयुक्त खाताधारकों और खाताधारक की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को धन तक पहुंच प्रदान करने के लिए "क्रामिक और एक साथ" नामांकन की शुरूआत शामिल है।

2 करोड़ रुपये तक की होलिडिंग वाले शेयरधारकों को अब पर्याप्त ब्याज माना जाएगा, जो पिछली 5 लाख रुपये की सीमा से अधिक है। [अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें](#)

8. भारत सरकार की हाल ही में (अगस्त'24 में) अधिसूचना के अनुसार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) और वित्तीय संस्थानों (FI) को 1 अगस्त, 2026 तक अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता कम से कम \_\_\_\_\_ तक बढ़ाने की आवश्यकता है।

- 1) 10%
- 2) 30%
- 3) 15%
- 4) 25%
- 5) 18%

उत्तर- 4) 25%

### स्पष्टीकरण:

सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) और वित्तीय संस्थानों (FI) के लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) मानदंडों का पालन करने की समय सीमा अगस्त 2026 तक बढ़ा दी है। यह विस्तार CPSE, PSB और FI को 1 अगस्त 2026 तक अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम 25% तक बढ़ाने की अनुमति देता है।

- वित्त मंत्रालय (MoF) ने जनहित में यह छूट प्रदान करते हुए एक ज्ञापन जारी किया। पहले के आदेश के अनुसार, दो साल की छूट **1 अगस्त, 2024** को समाप्त होनी थी।
- 31 मार्च, 2024 तक, 12 में से 7 PSB MPS मानदंड का अनुपालन कर रहे हैं, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) और बैंक ऑफ इंडिया (BoI) शामिल हैं।
- सरकार के स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को 10% सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने के लिए 16 मई, 2027 तक का समय दिया गया है।

**9. पुदुचेरी के मुख्यमंत्री (CM) N रंगासामी द्वारा 2 अगस्त 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-2025 (FY25) के लिए प्रस्तुत बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु 'सही' है/हैं?**

- A) पुदुचेरी के CM N रंगासामी ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 (FY25) के लिए 12,700 करोड़ रुपये का कर-मुक्त बजट पेश किया।  
 B) राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) सहित केंद्रीय सहायता 3,268.98 करोड़ रुपये अनुमानित है।  
 C) राजस्व व्यय 10,969.80 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, जबकि पूँजीगत व्यय 1,730.20 करोड़ रुपये है।

- 1) केवल A & B
- 2) केवल A & C
- 3) केवल B & C
- 4) केवल A
- 5) सभी A, B & C

उत्तर- 5) सभी A, B & C

**स्पष्टीकरण:**

i. 2 अगस्त, 2024 को पुदुचेरी के मुख्यमंत्री नटेसन कृष्णस्वामी रंगासामी (N रंगासामी), जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने पुदुचेरी के क्वाइट टाउन में 15वीं विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-2025 (FY25) के लिए 12,700 करोड़ रुपये का कर-मुक्त बजट पेश किया। यह उनका चौथा बजट था।

ii. राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) सहित केंद्रीय सहायता 3,268.98 करोड़ रुपये अनुमानित है।

iii. राजस्व व्यय 10,969.80 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, जबकि पूँजीगत व्यय 1,730.20 करोड़ रुपये है।

iv. केंद्रीय सड़क निधि 20 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 430 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

**10. हाल ही में (अगस्त'24 में) किस भारतीय मंत्रालय ने वायु, सड़क, रेल और जलमार्गों के माध्यम से मानव अंगों के निर्बाध परिवहन की सुविधा के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) शुरू की है?**

- 1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- 2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- 3) रेल मंत्रालय
- 4) नागरिक उड़ायन मंत्रालय
- 5) गृह मंत्रालय

उत्तर- 2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

**स्पष्टीकरण:**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने वायु, सड़क, रेल और जलमार्गों के माध्यम से मानव अंगों के निर्बाध परिवहन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) शुरू की है।

- प्राथमिक लक्ष्य अस्पतालों या शहरों के बीच जीवित अंगों के परिवहन में तेजी लाना है, जिससे अंगों के सीमित शेल्फ जीवन और कई एजेंसियों के सम्बन्ध की जटिलता के कारण समय पर डिलीवरी की महत्वपूर्ण आवश्यकता को संबोधित किया जा सके।

- SOP में अंगदानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं के अलग-अलग स्थानों पर होने पर अंगों के परिवहन के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिसमें हवाई यात्रा के लिए प्राथमिकता वाले उपाय, जैसे चिकित्सा कर्मियों के लिए विशेष व्यवस्था और एम्बुलेंस के लिए "ग्रीन कॉरिडोर" शामिल हैं।

**11. अगस्त 2024 में, भारत सरकार (GoI) ने \_\_\_\_\_ में आदिचुंचनगिरी को मोर अभ्यारण्य घोषित किया।**

- उत्तर प्रदेश
- हाराष्ट्र
- उत्तराखण्ड
- कर्नाटक
- केरल

उत्तर- 4) कर्नाटक

#### स्पष्टीकरण:

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने केरल के छूलन्नुअर और कर्नाटक के आदिचुंचनगिरी को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है।

- 1963 से भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की सुरक्षा के लिए MoEF&CC द्वारा प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- 1963 में, भारतीय परंपराओं में इसकी समृद्ध धार्मिक और पौराणिक भागीदारी के कारण मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था।
- यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत पूरी तरह से संरक्षित है।

**12. राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान (NIPCCD) के वर्तमान (अगस्त '24 तक) अध्यक्ष कौन हैं?**

- K. राधाकृष्णन
- अन्नपूर्णा देवी
- विजय कुमार सारस्वत
- सौम्या स्वामीनाथन
- अपूर्व चंद्रा

उत्तर- 2) अन्नपूर्णा देवी

#### स्पष्टीकरण:

महिला और बाल विकास मंत्रालय (**MWCD**), भारत सरकार (GOI) ने 50 से अधिक वर्षों के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट (**NIPCCD**) के कार्यकारी परिषद (EC) और जनरल बॉडी (GB) का पुनर्गठन किया है।

- केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, MWCD की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली, दिल्ली में आयोजित EC की एक बैठक और NIPCCD के GB की एक विशेष बैठक के दौरान पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।
- NIPCCD MWCD के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यह योजना आयोग के तत्वावधान में, सार्वजनिक सहयोग में केंद्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण के केंद्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण के रूप में जाना जाता है।
- GB में अब 94 से घटकर 22 सदस्य हो गए हैं और EC के 21 से घटकर 13 सदस्य रह गए हैं।
- केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी GB के अध्यक्ष और EC के अध्यक्ष हैं।

**13. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के नए शुरू किए गए सुराज्य मान्यता & रैंकिंग फ्रेमवर्क के चार स्तंभों से संबंधित नहीं है?**

- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- समृद्धि
- सुशासन
- किसान

## उत्तर- 5) किसान

### स्पष्टीकरण:

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MoC&I) द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय, भारत की गुणवत्ता परिषद (QCI), QCI

सूरज्या मान्यता & रैकिंग फांचे की शुरुआत कर रही है, जिसे विकसित भारत के लिए नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उत्कृष्टता को चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- इस फ्रेमवर्क को 4 स्तंभों, शिक्षा (एजुकेशन), स्वस्थ्य (हेल्थ), समृद्धि (प्रोस्पेरिटी) और सुशासन (गवर्नेंस) के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- सूरज्या मान्यता इन 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्यों और संगठनों द्वारा गुणवत्ता के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रतिबद्धता को स्वीकार करती है। [अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें](#)

14. किस कार्यक्रम/योजना ने हाल ही में (अगस्त'24 में) लीप डिज़ाइन्स के सहयोग से 'मिलियन डिज़ाइनर्स, बिलियन ड्रीम्स' पहल शुरू की है?

1) एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम

2) PM महिला शक्ति केंद्र स्कीम

3) महिला समृद्धि योजना

4) दीनदयाल अंत्योदय योजना-नेशनल रूरल लाइवलीहुडस मिशन

5) वन स्टॉप सेंटर (OSC) स्कीम

उत्तर- 4) दीनदयाल अंत्योदय योजना-नेशनल रूरल लाइवलीहुडस मिशन

### स्पष्टीकरण:

6 अगस्त 2024 को, दीनदयाल अंत्योदय योजना-नेशनल रूरल लाइवलीहुडस मिशन (**DAY-NRLM**) ने लीप डिज़ाइन्स के सहयोग से 'मिलियन डिज़ाइनर्स, बिलियन ड्रीम्स' पहल लॉन्च की। इस पहल का उद्देश्य जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिस्टम डिज़ाइन की जानकारी के साथ भारत भर के व्यक्तियों को सशक्त बनाना है।

- लॉन्च कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामीण आजीविका (RL), ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) के अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंह ने की।

15. अगस्त 2024 में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) के तहत \_\_\_\_\_ में 24x7 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया।

1) मनीमाजरा, चंडीगढ़

2) गुवाहाटी, असम

3) दुर्ग, छत्तीसगढ़

4) झाकरी, हिमाचल प्रदेश

5) नागपुर, महाराष्ट्र

उत्तर-1) मनीमाजरा, चंडीगढ़

### स्पष्टीकरण:

4 अगस्त 2024 को, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्रालय (MoHA) ने स्मार्ट सिटी मिशन (**SCM**) के तहत चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश (UT) में मनीमाजरा में 24x7 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी शामिल थे।

- यह परियोजना लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई और 15 वर्षों तक इसके रखरखाव के लिए 85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- इस परियोजना का उद्देश्य बेहतर जल गुणवत्ता, विश्वसनीयता और प्रभावी आपूर्ति-मांग प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

**16. उस स्व-नियामक निकाय का नाम बताइए जिसे हाल ही में (अगस्त'24 में) भारतीय स्वर्ण क्षेत्र द्वारा पहली बार स्थापित किया गया है।**

- 1) जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल
- 2) इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन
- 3) ज्वैलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
- 4) इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स
- 5) ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वैलरी काउंसिल ऑफ इंडिया

उत्तर- **4) इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स**

**स्पष्टीकरण:**

भारतीय स्वर्ण क्षेत्र ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (**WGC**) के सहयोग से उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देने के लिए इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स (**IAGES**) नामक पहला स्व-नियामक निकाय स्थापित किया।

- उद्देश्य: बुलियन उद्योग में निष्पक्ष, पारदर्शी और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- IAGES सोने के उद्योग की पूरी मूल्य शृंखला, यानी बुलियन व्यापार, रिफाइनरी और ट्रेडिंग से लेकर विनिर्माण, खुदरा बिक्री और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक को कवर करेगा।

**17. अगस्त 2024 में, इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉर्मर्स (IACC) के पहले “IACC-MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) उत्कृष्टता केंद्र (CoE)” का उद्घाटन \_\_\_\_\_ में किया गया।**

- 1) पुणे, महाराष्ट्र
- 2) चेन्नई, तमिलनाडु
- 3) अहमदाबाद, गुजरात
- 4) नई दिल्ली, दिल्ली
- 5) हैदराबाद, तेलंगाना

उत्तर- **3) अहमदाबाद, गुजरात**

**स्पष्टीकरण:**

8 अगस्त, 2024 को, गुजरात के मुख्यमंत्री (CM) भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद, गुजरात में KCG ऑडिटोरियम, i-HUB परिसर में इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉर्मर्स (IACC) के पहले “**IACC-MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) उत्कृष्टता केंद्र (CoE)**” का उद्घाटन किया।

- CoE का उद्देश्य MSME को वैश्विक निर्यात बाजारों के बराबर बनाने के लिए उन्हें उन्नत और मजबूत बनाना है।
- यह केंद्र भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के बीच औद्योगिक संबंधों को मजबूत करेगा।
- IACC-CoE को वैश्विक बाजारों में नेविगेट करने और अपनी निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए MSME को आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

**18. गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है?**

- 1) असम
- 2) उत्तराखण्ड
- 3) छत्तीसगढ़
- 4) केरल
- 5) ओडिशा

उत्तर- **3) छत्तीसगढ़**

**स्पष्टीकरण:**

छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व’ नाम से नए टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है, जो इसे छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व बना देगा।

- इंद्रावती टाइगर रिजर्व (बीजापुर), उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व (गरियाबंद) और अचानकमार टाइगर रिजर्व (मुंगेली) छत्तीसगढ़ के अन्य तीन टाइगर रिजर्व हैं।
- रिजर्व में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य के क्षेत्र शामिल होंगे, जो मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में 2,829.387 वर्ग किलोमीटर (sq km) के विशाल क्षेत्र को कवर करते हैं।

**19. 8 अगस्त, 2024 को हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा की गई मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु 'सही' है/हैं?**

A) प्रधानमंत्री JI-VAN (जैव ईंधन-पर्यावरण अनुकूल फसल आपदा निवारण) योजना में संशोधन, इसके कार्यान्वयन की समयसीमा को 5 वर्ष बढ़ाकर 2029-30 (FY30) करना।

B) FY25 से FY29 के दौरान 3,06,137 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) का कार्यान्वयन।

C) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoAFW) द्वारा 1,765.67 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रस्तावित स्वच्छ पौधा कार्यक्रम (CPP)

1) केवल A & B

2) केवल A & C

3) केवल B & C

4) केवल A

5) सभी A, B & C

उत्तर- 3) केवल B & C

**स्पष्टीकरण:**

i. 9 अगस्त, 2024 को भारत के प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है,

- प्रधान मंत्री JI-VAN (जैव ईंधन-वातावरन अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना में संशोधन, इसके कार्यान्वयन की समयसीमा को 5 साल बढ़ाकर 2028-29 (FY29) तक कर दिया गया है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों यानी FY25 से FY29 तक 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 को मंजूरी दी है, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश और 2.30 लाख करोड़ रुपये का सरकारी आवंटन है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने FY25 से FY29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाना है, जिसका कुल परिव्यय 3,06,137 करोड़ रुपये है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoAFW) द्वारा प्रस्तावित स्वच्छ पौध कार्यक्रम (CPP) को 1,765.67 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी है। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

**20. हाल ही में (अगस्त'24 में) किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र (UN) विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के साथ साझेदारी में भारत का पहला चौबीसों घंटे चलने वाला अनाज ATM, 'अन्नपुर्ति' लॉन्च किया है?**

1) उत्तराखण्ड

2) ओडिशा

3) केरल

4) राजस्थान

5) आंध्र प्रदेश

उत्तर- 2) ओडिशा

### स्पष्टीकरण:

ओडिशा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र (UN) विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के साथ 'ग्रेन ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM)' लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है, जिसे भुवनेश्वर (ओडिशा) में भारत का पहला राउंड-द-क्लॉक अनाज ATM अन्नपूर्ति के रूप में भी जाना जाता है।

- ओडिशा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) लाभार्थियों को 24/7 तक पहुंच प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
- अनाज ATM को 2022 में WFP इनोवेशन अवार्ड्स में भूख को खत्म करने के लिए WFP के शीर्ष 5 अभिनव समाधानों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी।
- यह 0.01% की त्रुटि दर के साथ पांच मिनट में 50 किलोग्राम (kg) तक का अनाज वितरित कर सकता है, जिससे प्रतीक्षा समय 70% कम हो जाता है।

21. अगस्त 2024 में, प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली, दिल्ली में \_\_\_\_\_ द्वारा विकसित 61 फसलों की 109 नई किस्में जारी कीं।

- 1) पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी
  - 2) इंडियन कॉउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च
  - 3) कृषि विज्ञान केंद्र
  - 4) एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी
  - 5) तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी
- उत्तर- 2) इंडियन कॉउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च

### स्पष्टीकरण:

11 अगस्त 2024 को, प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने ICAR-इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टिट्यूट (ICAR), पूसा, नई दिल्ली, दिल्ली में इंडियन कॉउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) द्वारा विकसित 61 फसलों की 109 नई किस्मों का विमोचन किया।

- 61 फसलों की उच्च पैदावार, जलवायु लचीला और बायोफोर्टिफाइड किस्मों में 34 फील्ड फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं।
- ये किस्में पोषण से भरपूर और पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूल हैं।

22. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस (LF) को खत्म करने के लिए तैयार है?

- 1) 2030
- 2) 2029
- 3) 2028
- 4) 2025
- 5) 2027

उत्तर- 5) 2027

### स्पष्टीकरण:

राज्य मंत्री (MoS) (स्वतंत्र प्रभार, IC) प्रतापराव गणपतराव जाधव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया (LF) को खत्म करने के लिए द्वि-वार्षिक राष्ट्रव्यापी जन औषधि प्रशासन (MDA) अभियान 2024 के दूसरे चरण का वस्तुतः शुभारंभ किया। LF को आमतौर पर एलिफेटियासिस (हाथीपांव) प्राथमिकता वाले मच्छर जनित रोग के रूप में जाना जाता है।

- इस लॉन्च में 'रिवाइज्ड गाइडलाइन ऑन एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस' और LF उन्मूलन के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) सामग्री का विमोचन शामिल था।
- अभियान बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश (UP) के 63 स्थानिक जिलों पर केंद्रित है।

**23. किस विभाग ने हाल ही में (अगस्त'24 में) राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) अभियान 3.0 के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं?**

- 1) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
- 2) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- 3) वित्तीय सेवा विभाग
- 4) पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग
- 5) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

उत्तर- **4) पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग**

**स्पष्टीकरण:**

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (MoPP&P) के अंतर्गत पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (DLC) अभियान 3.0 के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं, जो 1-30 नवंबर, 2024 तक पूरे भारत के 800 शहरों/जिलों में आयोजित किया जाएगा।

- पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए हर साल नवंबर में अपना जीवन प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।
- अभियान की निगरानी DLC अभियान पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर की जाएगी, जिसमें PDB विस्तृत योजनाएँ तैयार करेंगे और PWA के साथ समन्वय करेंगे।

**24. निम्नलिखित में से कौन सी तीन हिंद महासागर भौगोलिक संरचनाएँ हैं जिनका नाम इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक आर्गेनाइजेशन (IHO) और UNESCO के अंतर-सरकारी महासागरीय आयोग (IOC) द्वारा रखा गया है?**

**A) अशोक सीमाउंट**

**B) चंद्रगुप्त रिज**

**C) कल्पतरु रिज**

1) केवल A & B

2) केवल A & C

3) केवल B & C

4) केवल A

5) सभी A, B & C

उत्तर- **5) सभी A, B & C**

**स्पष्टीकरण:**

UNESCO (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) के इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक आर्गेनाइजेशन (IHO) और अंतर-सरकारी महासागरीय आयोग (IOC) ने हिंद महासागर में स्थित तीन पानी के नीचे की भौगोलिक संरचनाओं को अशोक सीमाउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज नाम दिया है।

- संरचना के नाम भारत द्वारा IHO और IOC को प्रस्तावित किए गए थे।
- अशोक सीमाउंट और चंद्रगुप्त रिज का नाम क्रमशः मौर्य वंश के शासकों अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर रखा गया है।

i. इन तीन संरचनाओं की खोज राष्ट्रीय ध्वीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR), गोवा के समुद्र विज्ञानियों द्वारा की गई थी।

ii. हिंद महासागर के दक्षिण-पश्चिम भारतीय रिज क्षेत्र के साथ स्थित इन संरचनाओं की खोज भारतीय दक्षिणी महासागर अनुसंधान कार्यक्रम के दौरान की गई थी। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

**25. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने हाल ही में (अगस्त '24 में) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) को ONGC पेट्रो परिवर्धन लिमिटेड (OPaL) में \_\_\_\_\_ तक की अतिरिक्त इकिटी पूँजी निवेश करने की मंजूरी दी है।**

- 1) 4,958 करोड़ रुपये
- 2) 10,501 करोड़ रुपये
- 3) 4,630 करोड़ रुपये
- 4) 7453 करोड़ रुपये
- 5) 8754 करोड़ रुपये

**उत्तर-2) 10,501 करोड़ रुपये**

**स्पष्टीकरण:**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (**MoPNG**), भारत सरकार (GoI) ने ONGC पेट्रो परिवर्धन लिमिटेड (**OPaL**), वडोदरा (गुजरात) में **10,501 करोड़ रुपये** तक की अतिरिक्त इकिटी पूँजी का निवेश करने के लिए MoPNG के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (**ONGC**) को एक अनुमोदन पत्र प्रदान किया है।

- OPaL एक संयुक्त उद्यम (JV) है जो ONGC, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया (GAIL), और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (GSPC) के बीच है।
- GoI ने 7,778 करोड़ रुपये के बैक-स्टॉप अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (CCD) के रूपांतरण और शेयर वारंट से संबंधित 86 करोड़ रुपये के शेष भुगतान को भी मंजूरी दे दी है, जो कुल 18,365 करोड़ रुपये है।
- इससे OPaL की स्थिति ONGC की सहायक कंपनी में 49.36% इकिटी हिस्सेदारी से 95.69% इकिटी हिस्सेदारी के साथ बढ़ जाएगी।

**26. निम्नलिखित में से किस आर्द्धभूमि को हाल ही में (अगस्त '24 में) रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है?**

- A) नांजरायण पक्षी अभ्यारण्य
- B) काङ्गुवेली पक्षी अभ्यारण्य

**C) तवा जलाशय**

- 1) केवल A & B
- 2) केवल A & C
- 3) केवल B & C
- 4) केवल A
- 5) सभी A, B & C

**उत्तर- 5) सभी A, B & C**

**स्पष्टीकरण:**

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (**MoEF&CC**) ने घोषणा की कि भारत से **3 आर्द्धभूमि** अर्थात् तमिलनाडु (TN) में **नांजरायण पक्षी अभ्यारण्य** और **काङ्गुवेली पक्षी अभ्यारण्य** और मध्य प्रदेश (MP) में तवा जलाशय को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्धभूमि के रूप में नामित किया गया है, जिसे रामसर साइट्स भी कहा जाता है।

- इसके साथ, भारत में रामसर स्थलों की संख्या **85** हो जाती है, जो 1,358,068 हेक्टेयर (Ha) के क्षेत्र को कवर करती है।
- TN में सबसे अधिक रामसर स्थल (18) हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश (UP) (10) का स्थान है। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

27. नए शुरू किए गए अपतटीय क्षेत्र खनिज न्यास नियम, 2024 के अनुसार, अपतटीय खदानों के उत्पादन पट्टाधारकों को अपने रॉयल्टी भुगतान का \_\_\_\_\_ हिस्सा न्यास को देना होगा।

- 1) 15%
- 2) 10%
- 3) 25%
- 4) 5%
- 5) 20%

उत्तर-2) 10%

#### स्पष्टीकरण:

खान मंत्रालय, भारत सरकार (**GoI**) ने अपतटीय क्षेत्र खनिज न्यास नियम, 2024 पेश किए हैं, जो भारत के अपतटीय क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण और उत्पादन की देखरेख के लिए पहली बार ढांचा स्थापित किया है।

- नए नियमों के तहत, अपतटीय खदानों के उत्पादन पट्टाधारकों को अपने रॉयल्टी पेमेंट का **10%** न्यास को देना होगा।
- यह राशि भारत के सार्वजनिक खाते (**PAI**) में जमा की जाएगी, जिससे न्यास की वित्तीय नींव मजबूत होगी।
- न्यास का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए सतत अन्वेषण को बढ़ावा देना है।
- खान मंत्रालय ने संभावित नीलामी के लिए 10 अपतटीय खनिज ब्लॉकों की पहचान की है, जिसके लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श वर्तमान में चल रहा है।

28. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (**MoPNG**) ने ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड के नामित क्षेत्रों में नए कुओं या कुओं के हस्तक्षेप से उत्पादित प्राकृतिक गैस के लिए विनियमित प्रशासित मूल्य तंत्र (**APM**) मूल्य पर कितने प्रतिशत प्रीमियम को मंजूरी दी है?

- 1) 50%
- 2) 27%
- 3) 35%
- 4) 32%
- 5) 20%

उत्तर-5) 20%

#### स्पष्टीकरण:

12 अगस्त 2024 को, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (**MoPNG**) ने राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों - तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (**ONGC**), नई दिल्ली (दिल्ली) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (**OIL**), नोएडा, उत्तर प्रदेश (UP) के नामित क्षेत्रों में नए कुओं या कुओं के हस्तक्षेप से उत्पादित किसी भी प्राकृतिक गैस के लिए विनियमित या प्रशासित मूल्य तंत्र (**APM**) मूल्य पर **20%** प्रीमियम को मंजूरी दी है।

- इस कदम से फर्मों को नई गैस विकास परियोजनाओं को अधिक व्यवहार्य बनाने और नामित क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- अधिसूचना के अनुसार, ONGC और OIL के नामित क्षेत्रों से उत्पादित गैस को कच्चे तेल की कीमत से जुड़ी मौजूदा नीति के तहत भारतीय कच्चे तेल की टोकरी की कीमत का कुल 12% प्रीमियम मिलेगा।

**29. भारत सरकार द्वारा आयोजित 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में से कौन सा/से बिंदु 'सही' है/हैं?**

A) भारत के प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और अपना लगातार 11वां स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया।

B) भारत की राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के कर्मियों को 103 वीरता पुरस्कारों (9 मरणोपरांत सहित) को मंजूरी दी।

C) पंजाब रेजिमेंट मिलिट्री बैंड ने सूबेदार मेजर राजिंदर सिंह के नेतृत्व में ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रगान बजाया।

1) केवल A & B

2) केवल A & C

3) केवल B & C

4) केवल A

5) सभी A, B & C

उत्तर- 5) सभी A, B & C

**स्पष्टीकरण:**

i. भारत सरकार ने नई दिल्ली, दिल्ली में लाल किला में 78 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया है। भारत के प्रधान मंत्री (PM) ने राष्ट्र को संबोधित किया और अपने लगातार 11 वें स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया।

- 2024 के स्वतंत्रता दिवस के लिए थीम 'विकसित भारत@2047' निर्धारित की गई है, अर्थात् 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना।
- यह उनके तीसरे कार्यकाल का पहला पता था।

ii. PM के लिए गार्ड ऑफ ऑनर में भारतीय सेना (IA), भारतीय नौसेना (IN), भारतीय वायु सेना (IAF), और दिल्ली पुलिस के अधिकारी और 24 कर्मी शामिल थे। IN 2024 में समन्वय सेवा है।

iii. भारत की राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) कर्मियों को 103 वीरता पुरस्कारों (9 मरणोपरांत सहित) को मंजूरी दी।

iv. पंजाब रेजिमेंट मिलिट्री बैंड ने सूबेदार मेजर राजिंदर सिंह के नेतृत्व में ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रगान बजाया।

अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें

**30. किस मंत्रालय ने हाल ही में (अगस्त'24 में) ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम (GTTP) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) शुरू की है?**

1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

4) भारी उद्योग मंत्रालय

5) बंदरगाह, नौवहन & जलमार्ग मंत्रालय

उत्तर- 5) बंदरगाह, नौवहन & जलमार्ग मंत्रालय

**स्पष्टीकरण:**

केंद्रीय मंत्री सर्वानन्द सोनोवाल, बंदरगाह, जहाजरानी & जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW), ने नई दिल्ली, दिल्ली में ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम (GTTP) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया।

- इस पहल का उद्देश्य प्रमुख भारतीय बंदरगाहों में पारंपरिक ईंधन-आधारित टगों को पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों के साथ बदलना है, जो पर्यावरणीय स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है।
- GTTP को भारतीय बंदरगाहों में संचालित पारंपरिक ईंधन-आधारित हार्बर टगों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और उन्हें स्वच्छ और अधिक टिकाऊ वैकल्पिक ईंधन द्वारा संचालित ग्रीन टगों से बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- GTTP के चरण 1 (1 अक्टूबर 2024 - 31 दिसंबर 2027) में 4 प्रमुख बंदरगाह शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक स्थायी विनिर्देश समिति (SSC) द्वारा जारी मानकीकृत डिजाइनों और विनिर्देशों के आधार पर कम से कम 2 ग्रीन टग खरीदेगा या किराए पर लेगा।

**31. किस राज्य ने हाल ही में (अगस्त '24 में) रत्नागिरी में पेट्रोग्लिफ्स और जियोग्लिफ्स (रॉक आर्ट) को 'संरक्षित स्मारक' घोषित किया है?**

- 1) उत्तराखण्ड
- 2) उत्तर प्रदेश
- 3) मध्य प्रदेश
- 4) महाराष्ट्र
- 5) कर्नाटक

**उत्तर- 4) महाराष्ट्र**

**स्पष्टीकरण:**

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1960 के तहत रत्नागिरी में पेट्रोग्लिफ्स और जियोग्लिफ्स (रॉक आर्ट) को 'संरक्षित स्मारक' घोषित किया है।

- जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स प्राचीन आर्ट के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें पृथ्वी की सतह या चट्टान की सतह पर छवियों या डिज़ाइनों का निर्माण शामिल है।
- रत्नागिरी में 70 स्थलों पर फैली लगभग 1,500 ऐसी कलाकृतियाँ हैं, जिनमें से सात संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) की संभावित विश्व विरासत सूची (WHL) में हैं।
- पेट्रोग्लिफ्स देउद, रत्नागिरी (महाराष्ट्र) में पाए जाते हैं, जो मेसोलिथिक युग (लगभग 20,000-10,000 साल पहले) के हैं।
- जियोग्लिफ्स महाराष्ट्र और गोवा में 900 किलोमीटर (km) के कोंकण तट पर स्थित है।

**32. 16 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु 'सही' है/हैं?**

- A) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वर्गेट से कटराज तक 5.46 किलोमीटर (km) तक पुणे मेट्रो फेज-1 प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी।
- B) इसने महाराष्ट्र में वधवन बंदरगाह के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (NH)-48 तक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क को मंजूरी दी।
- C) इसने बिहार में बागडोगरा हवाई अड्डे और पश्चिम बंगाल में बिहटा हवाई अड्डे पर दो नए सिविल एन्क्लेव के विकास को भी मंजूरी दी।

- 1)केवल A & B
- 2)केवल A & C
- 3)केवल B & C
- 4)केवल B
- 5)सभी A, B & C

**उत्तर- 1)केवल A & B**

**स्पष्टीकरण:**

16 अगस्त 2024 को, भारत के प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च प्रभाव वाली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शृंखला को मंजूरी दी है:

i. स्वर्गेट से कटराज तक पुणे मेट्रो फेज-1 प्रोजेक्ट का विस्तार, जिसकी लंबाई 5.46 km होगी।

ii. महाराष्ट्र में ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का विकास।

iii. 31 स्टेशनों के साथ 44.65 km के लिए बैंगलोर मेट्रो रेल फेज-3 प्रोजेक्ट के दो कॉरिडोर।

iv. PM मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) ने पश्चिम बंगाल (WB) में बागडोगरा हवाई अड्डे और बिहार में बिहटा हवाई अड्डे पर दो नए नागरिक परिक्षेत्रों के विकास को भी मंजूरी दी।

v. महाराष्ट्र में वधावन बंदरगाह के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (NH)-48 तक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क। [अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें](#)

33. हाल ही में (अगस्त'24 में) तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री (CM) कलैगनार मुथुवेल करुणानिधि की जन्म शताब्दी के अवसर पर जारी किए गए सिक्के का मूल्य क्या था?

- 1) 75 रुपये
- 2) 250 रुपये
- 3) 100 रुपये
- 4) 150 रुपये
- 5) 90 रुपये

उत्तर- 3) 100 रुपये

स्पष्टीकरण:

18 अगस्त 2024 को, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय (MoD) ने तमिलनाडु (TN) के पूर्व मुख्यमंत्री (CM) कलैगनार मुथुवेल करुणानिधि की जन्म शताब्दी के अवसर पर **100 रुपये** का स्मारक सिक्का जारी किया।

- यह सिक्का चेन्नई (TN) के कलैवनार आरंगम में तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जारी किया गया।
- सिक्के के पीछे की तरफ करुणानिधि का चित्र और तमिल नारा 'तमिल वेल्लुम' (तमिल विंस) के साथ हिंदी और अंग्रेजी में "कलैगनार करुणानिधि की जन्म शताब्दी" लिखा हुआ है।
- 100 रुपये के सिक्के का वजन 35 ग्राम है, इसका व्यास 44 मिलीमीटर है, जिसके किनारे पर 200 दाँते हैं।
- यह 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जस्ता युक्त मिश्र धातु से बना होगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई, TN में भारतीय तटरक्षक (ICG) के नए सामुद्रिक बचाव समन्वय केंद्र (MRCC) का उद्घाटन किया।

- उन्होंने चेन्नई में क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र (RMPRC) और पुदुचेरी में कोस्ट गार्ड एयर एन्क्लेव (CGAE) का भी वर्चुअली शुभारंभ किया।

34. किस संगठन ने हाल ही में (अगस्त'24 में) इंडिया-ऑस्ट्रेलिया रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन (RISE) एक्सेलरेटर प्रोग्राम के क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक कोहोर्ट को लॉन्च करने के लिए कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (CSIRO) के साथ साझेदारी की है?

- 1) स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
- 2) कॉउन्सिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
- 3) अटल इनोवेशन मिशन
- 4) एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी
- 5) इंडियन कॉउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च

उत्तर- 3) अटल इनोवेशन मिशन

स्पष्टीकरण:

19 अगस्त 2024 को, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI आयोग) समर्थित अटल इनोवेशन मिशन (AIM) ने ऑस्ट्रेलिया सरकार की एक शाखा कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (CSIRO) के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन (RISE) एक्सेलरेटर प्रोग्राम के क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक कोहोर्ट को लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम के लिए स्टार्टअप्स और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

- उद्देश्य: कृषि में जलवायु चुनौतियों का समाधान करने और सीमा पार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और डिजिटल समाधानों का उपयोग करना।
- कोहोर्ट को विशेष रूप से कृषि उत्पादकता और लचीलेपन में सुधार करने वाली तकनीकों और समाधानों के साथ काम करने वाले स्टार्टअप्स और MSME को सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

35. हाल ही में (अगस्त'24 में) किस कंपनी ने उचित मूल्य की दुकानों (FPS) को जन पोषण केंद्रों (JPK) में बदलने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (MOCAF&PD) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के साथ भागीदारी की है?

- 1) अमेज़न
- 2) JioMart
- 3) फिलिपकार्ट
- 4) उड़ान
- 5) IndiaMART

उत्तर- 4) उड़ान

#### स्पष्टीकरण:

उड़ान, एक B2B(बिजनेस टू बिजनेस) ई-कॉर्मस कंपनी, ने उचित मूल्य की दुकानों (FPS) को जन पोषण केंद्रों (JPK) में बदलने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (MOCAF&PD) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के साथ साझेदारी की है।

- इस साझेदारी का उद्देश्य FPS डीलरों की आय में वृद्धि करना और इन दुकानों द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों के पोर्टफोलियो में सुधार करना है।
- इस पायलट परियोजना को राजस्थान, उत्तर प्रदेश (UP), तेलंगाना और गुजरात के 60 चयनित FPS में लॉन्च किया गया है।
- इस साझेदारी के तहत, जन पोषण केंद्रों को खाद्यान्न और फास्ट-मूर्विंग कंज्युमर गुड्स (FMCG) उत्पादों की खरीद के लिए SIDBI से ऋण सुविधाएं मिलेंगी और उड़ान के eB2B प्लेटफॉर्म के माध्यम से 3,500 से अधिक उत्पादों तक पहुंच मिलेगी।
- इस पहल का उद्देश्य अंततः 1.3 लाख दुकानों का आधुनिकीकरण करना है, जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य सभी 5.38 लाख राशन दुकानों को JPK में बदलना है।

36. अगस्त 2024 में, उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (NEHHDC) ने अपने

(उत्पाद) के लिए ऑको-टेक्स सर्टिफिकेशन प्राप्त किया।

- 1) रिमार्ई
- 2) गमसा
- 3) ज्वमग्रा
- 4) वांगखेई फी
- 5) एरी सिल्क

उत्तर- 5) एरी सिल्क

#### स्पष्टीकरण:

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) के तहत गुवाहाटी (অসম) स्थित उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (NEHHDC) ने असम के एरी सिल्क के लिए सीधे जर्मनी से ऑको-टेक्स सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है।

- ऑको-टेक्स सर्टिफिकेशन मानक 100 यह सुनिश्चित करता है कि वस्त्रों का हानिकारक पदार्थों के लिए परीक्षण किया जाता है और पर्यावरण के अनुकूल परिस्थितियों में उत्पादन किया जाता है।
- एरी सिल्क अपनी नैतिक विनिर्माण प्रक्रिया के कारण दुनिया के एकमात्र वीगन सिल्क के रूप में प्रसिद्ध है। यह पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया एरी सिल्क को कपड़ा उद्योग में करुणा और स्थिरता का प्रतीक बनाती है।
- यह उपलब्धि सिल्क की स्थिति को असम के भौगोलिक संकेत (GI) उत्पाद के रूप में और मजबूत करती है, जो इसकी प्रामाणिकता और क्षेत्रीय प्रासंगिकता पर जोर देती है।

**37. किस मंत्रालय ने हाल ही में (अगस्त'24 में) घरेलू सर्वेक्षण प्रभाग और उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग नामक प्रभाग बनाए हैं?**

- 1) वित्त मंत्रालय
  - 2) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
  - 3) कानून और न्याय मंत्रालय
  - 4) आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय
  - 5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- उत्तर- 5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

**स्पष्टीकरण:**

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने अपने कामकाज का पुनर्गठन किया है और दो सर्वेक्षण-वार वर्टिकल बनाए हैं, जिसका उद्देश्य आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) जैसे विभिन्न सर्वेक्षणों की आवृत्ति को बढ़ाना और उन्हें जारी करने में समय अंतराल को कम करना है।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक सर्वेक्षण अभ्यास में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों का पालन किया जाता है, इसने घरेलू और उद्यम सर्वेक्षणों के लिए प्रभागों का सृजन करने के अलावा राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इकाइयों को अपने मौजूदा इंट्रा, इंटर और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन (II & IC) यूनिट से अलग कर दिया है।

**38. किस कंपनी ने हाल ही में (अगस्त'24 में) तमिलनाडु (TN) के थूथुकुड़ी में भारत के पहले ग्रीन अमोनिया विनिर्माण इकाई के लिए 36,238 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की है?**

- 1) सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज
  - 2) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
  - 3) HHP फाइव प्राइवेट लिमिटेड
  - 4) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  - 5) वेदांता लिमिटेड
- उत्तर- 1) सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज

**स्पष्टीकरण:**

सिंगापुर स्थित सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज तमिलनाडु (TN) के थूथुकुड़ी में ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 36,238 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

- TN भारत का पहला राज्य होगा जो बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन अणुओं का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेगा।
- इस इकाई की आधारशिला TN के मुख्यमंत्री (CM) M.K. स्टालिन (मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन) ने 21 अगस्त 2024 को चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित तमिलनाडु निवेश सम्मेलन 2024 के दौरान रखी थी।

**39. किस देश ने हाल ही में (अगस्त'24 में) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान - बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (IIT-BHU) के साथ वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्वच्छ नदियों पर एक स्मार्ट प्रयोगशाला (SLCR) परियोजना शुरू करने के लिए साझेदारी की है?**

- 1) जापान
  - 2) डेनमार्क
  - 3) अज़रबैजान
  - 4) इंडिया
  - 5) सिंगापुर
- उत्तर- 2) डेनमार्क

### स्पष्टीकरण:

नई दिल्ली (दिल्ली) स्थित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (**NMCG**), वाराणसी, उत्तर प्रदेश (UP) स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान - बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (**IIT-BHU**), और डेनमार्क सरकार ने वाराणसी, उत्तर प्रदेश (UP) में स्वच्छ नदियों पर एक स्मार्ट प्रयोगशाला (**SLCR**) परियोजना शुरू की है।

- यह पहल भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नवीन और टिकाऊ दृष्टिकोणों के माध्यम से छोटी नदियों का कायाकल्प करना है।
- उद्देश्य: SLCR परियोजना का उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता का लाभ उठाकर वरुणा नदी का कायाकल्प करना है।
- SLCR सचिवालय को जल शक्ति मंत्रालय (**MoJS**) से प्रारंभिक वित्त पोषण में **16.80 करोड़ रुपये** मिलेंगे, साथ ही दीर्घकालिक स्थिरता और परियोजना विकास को बढ़ाने के लिए डेनमार्क से **5 करोड़ रुपये** का अनुदान मिलेगा। [अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें](#)

40. अगस्त 2024 में, भारत सरकार (GoI) ने \_\_\_\_\_ तक 100% ZET बिक्री पैठ हासिल करने के उद्देश्य से "भारत जीरो एमिशन ट्रॉकिंग (ZET) पॉलिसी एडवाइजरी" दस्तावेज़ लॉन्च किया।

- 1) 2045
- 2) 2040
- 3) 2050
- 4) 2060
- 5) 2055

उत्तर- 3) 2050

### स्पष्टीकरण:

21 अगस्त 2024 को, भारत सरकार (GoI) के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने नई दिल्ली, दिल्ली में विज्ञान भवन एनेक्सी में "[भारत जीरो एमिशन ट्रॉकिंग \(ZET\) पॉलिसी एडवाइजरी](#)" दस्तावेज़ लॉन्च किया।

- यह परामर्श **2050 तक 100% ZET बिक्री पैठ हासिल करने** के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करता है, जो भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है।
- सलाहकार का विकास एक पॉलिसी एडवाइजरी पैनल (**PAP**) द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता PSA कार्यालय की सलाहकार डॉ. प्रीति बंजल ने की थी; और विभिन्न उद्योग और शैक्षणिक नेताओं के योगदान के साथ PSA फेलो प्रोफेसर कार्तिक आत्मनाथन ने इसकी उपाध्यक्षता की थी।
- PAP के मार्गदर्शन में पॉलिसी एडवाइजरी दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (**IIT**) मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जीरो एमिशन ट्रॉकिंग (**CoEZET**) में एक परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की गई थी।

41. नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू (JN) बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (**MoPSW**) द्वारा शुरू की गई सतत पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु सही है/हैं?

- A) महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संतों, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत एकनाथ महाराज और संत नामदेव महाराज के सम्मान में नामित तीन नव पुनर्जीवित मीठे पानी की झीलों का उद्घाटन किया गया।
- B) जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (JNPA), वधवन बंदरगाह और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए ऋण के वितरण के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए।
- C) JNPA और गेटवे टर्मिनल इंडिया (GTI) ने बंदरगाह के जहाजों के लिए बिजली की आपूर्ति को बढ़ाकर सतत प्रयास को बढ़ावा देने के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए।

- 1) केवल A & B
- 2) केवल B & C
- 3) केवल A & C

4) केवल A

5) सभी A, B & C

उत्तर- 5) सभी A, B & C

#### स्पष्टीकरण:

22 अगस्त 2024 को, केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने महाराष्ट्र के नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू (JN) बंदरगाह पर तीन नए पुनर्जीवित मीठे पानी की झीलों का उद्घाटन करने के बाद प्रमुख सतत पहल की शुरुआत की।

- महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संतों, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत एकनाथ महाराज और संत नामदेव महाराज के सम्मान में नामित झीलें वर्षा जल संचयन और आवास बहाली के लिए महत्वपूर्ण जलाशयों के रूप में काम करेंगी।
- जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (JNPA), वधवन बंदरगाह और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए ऋण के वितरण के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए।
- JNPA और गेटवे टर्मिनल इंडिया (GTI) ने बंदरगाह के जहाजों के लिए बिजली आपूर्ति को बढ़ावा देकर सतत प्रयास को बढ़ावा देने के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए।
- केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने महाराष्ट्र के मुंबई में JN बंदरगाह पर आयोजित एक समारोह में स्मार्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) परियोजना का शुभारंभ किया।
- JNPA ने एडिशनल लिकिड कार्गो बर्थ (ALCB) यानी लिकिड बर्थ-3 (LB3) और बर्थ-4 (LB4) की शुरुआत के साथ अपनी लिकिड कार्गो हैंडलिंग क्षमता के सफल विस्तार की घोषणा की। [अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें](#)

42. हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने \_\_\_\_\_ को मनाए गए 165वें आयकर दिवस के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया।

1) 24 अगस्त 2024

2) 24 अप्रैल 2024

3) 24 जुलाई 2024

4) 24 मई 2024

5) 24 जून 2024

उत्तर- 3) 24 जुलाई 2024

#### स्पष्टीकरण:

21 अगस्त 2024 को, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्रालय (MoF) ने भारत में आयकर (IT) के 165 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, नई दिल्ली, दिल्ली में 'माई स्टैम्प - 165th इनकम टैक्स डे' जारी किया। यह स्टैम्प आयकर दिवस की 165वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान जारी किया गया।

- भारत में आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है, जो 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में आयकर की शुरुआत की याद में मनाया जाता है। 24 जुलाई 2024 को 165वां आयकर दिवस मनाया जाएगा।
- कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने आयकर विभाग की टीम को 'CBDT उत्कृष्टा प्रमाणपत्र' प्रदान किया, जिसने ओडिशा में एक डिस्टिलरी समूह के खिलाफ 2023 में छापेमारी में भारत में अब तक की सबसे अधिक लगभग 352 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की।

43. 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु सही है/हैं?

A) UPS के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने वेतन का 10% योगदान देंगे जबकि केंद्र सरकार 14% योगदान देगी।

B) UPS के तहत, सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी जिन्होंने न्यूनतम 25 वर्षों तक सेवा की है, उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों से अपने अंतिम आहरित वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा।

C) अप्रैल 2023 में पूर्व वित्त सचिव T.V. सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति ने UPS की सिफारिश की थी।

1) केवल A & B

2) केवल A & C

3) केवल B & C

4) केवल A

5) सभी A, B & C

उत्तर- 3) केवल B & C

#### स्पष्टीकरण:

PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी है। UPS मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) के लाभों को जोड़ती है।

- यह योजना **1 अप्रैल, 2025** से लागू होगी। UPS का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो 31 मार्च, 2025 तक NPS के तहत सेवानिवृत्त हो चुके हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
- महाराष्ट्र सरकार** अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जो मार्च 2024 से प्रभावी होगी।
- अप्रैल, 2023 में पूर्व वित्त सचिव **T.V. सोमनाथन** की अध्यक्षता वाली समिति ने UPS की सिफारिश की थी।
- UPS के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की तरह अपने वेतन का **10%** योगदान देना जारी रखेंगे। जबकि, केंद्र सरकार ने अपना योगदान 14% (वर्तमान में NPS के तहत) से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है।
- सुनिश्चित पेंशन:** UPS के तहत, सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी जिन्होंने न्यूनतम **25 वर्षों** तक सेवा की है, उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों से अपने अंतिम आहरित वेतन का **50%** पेंशन के रूप में प्राप्त होगा।
- सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन:** इस योजना में उन कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन की एक अनूठी विशेषता है, जिन्होंने कम से कम **10 वर्षों** तक सेवा की है, वे सेवानिवृत्ति पर प्रति माह **10,000** रुपये का न्यूनतम पेंशन लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

i. भारत के प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है:

ii. 24 अगस्त 2024 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoS&T) के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की एक नई एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना, "विज्ञान धारा" के तहत **3** अम्बेला योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी दी है।

- 15वें वित्त आयोग के दौरान यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 (FY22) से FY26 तक योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित बजट **10, 579.84 करोड़** रुपये है।

iii. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकॉनमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट (**BioE3**) नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoS&T) के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के उच्च प्रदर्शन वाले जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

- BioE3 नीति तीन कार्यान्वयन रणनीतियों:** खोज और एकीकृत अनुसंधान नेटवर्क, मौजूदा अंतराल को पाटना और बायो-सक्षम केंद्र स्थापित करने की रूपरेखा तैयार करती है। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

**44. निम्नलिखित में से कौन सा लद्धाख के केंद्र शासित प्रदेश (UT) में नए बनाए गए पांच जिलों में से एक नहीं है?**

- 1) ज़ांस्कर
- 2) द्रास
- 3) नुब्रा
- 4) चांगथांग
- 5) हेमिस

उत्तर- 5) हेमिस

**स्पष्टीकरण:**

गृह मंत्रालय (MHA) ने लद्धाख के केंद्र शासित प्रदेश (UT) में 5 नए जिलों, अर्थात् ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग के निर्माण की घोषणा की। नए जिलों के गठन के साथ, लद्धाख की कुल संख्या बढ़कर 7 हो गई है।

- MHA ने लद्धाख प्रशासन को मुख्यालय, सीमाओं और नए जिलों की संरचना जैसे पहलुओं का मूल्यांकन करने और 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया।
- वर्तमान में, लद्धाख में केवल 2 जिले हैं, लेह और कारगिल, दोनों का प्रबंधन इसकी स्वायत्त जिला परिषद द्वारा किया जाता है।
- लद्धाख अपनी आदिवासी पहचान, संस्कृति, भूमि और संसाधनों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है।

**45. 28 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से 'सही' है/हैं?**

A) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी FM रेडियो चरण III नीति के तहत 784.87 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के साथ 234 नए शहरों में 730 निजी FM (फ्रीकैंसी मॉड्यूलेशन) रेडियो चैनल स्थापित करने के लिए आरोही ई-नीलामी के तीसरे बैच के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

B) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 3 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दो नई लाइनें और एक मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना जिसकी कुल अनुमानित लागत 6,456 करोड़ रुपये है।

C) CCEA ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के तहत 25,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 10 नए औद्योगिक नोड्स/शहरों को मंजूरी दी है।

- 1) केवल A & B
- 2) केवल B & C
- 3) केवल A & C
- 4) केवल A
- 5) सभी A, B & C

उत्तर- 1) केवल A & B

**स्पष्टीकरण:**

प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी:

i. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के तहत केंद्रीय क्षेत्र योजना (CSS) के प्रगतिशील विस्तार को मंजूरी दी। विस्तार का उद्देश्य पात्र परियोजनाओं को व्यापक बनाकर और सहायक उपायों को जोड़कर योजना को अधिक आकर्षक, प्रभावशाली और समावेशी बनाना है।

ii. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी FM रेडियो चरण III नीति के तहत 784.87 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के साथ 234 नए शहरों में 730 निजी FM (फ्रीकैंसी मॉड्यूलेशन) रेडियो चैनल स्थापित करने के लिए आरोही ई-नीलामी के तीसरे बैच के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

iii. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं में इक्किटी भागीदारी के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में राज्य सरकारों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान करने के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

iv. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 6,456 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत के साथ 3 रेलवे परियोजनाओं अर्थात् दो नई लाइनों और एक मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य

कनेक्टिविटी में सुधार करना, यात्रा को आसान बनाना, रसद लागत को कम करना और पूरे भारत में CO<sub>2</sub> उत्सर्जन को कम करना है।

v.CCEA ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (**NICDP**) के तहत **28,602** करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 12 नए औद्योगिक नोड्स/शहरों को मंजूरी दी है। [अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें](#)

**46.** हाल ही में (अगस्त'24 में) लॉन्च की गई व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी या वोलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (**VVMP**) के अनुसार, राज्य सरकारें गैर-परिवहन व्हीकल्स के लिए \_\_\_\_\_ तक के मोटर व्हीकल कर पर रियायत देंगी।

- 1) 50%
- 2) 6%
- 3) 28%
- 4) 25%
- 5) 12%

उत्तर- **4) 25%**

**स्पष्टीकरण:**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (**MoRTH**) ने पूरे भारत में अनुपयुक्त प्रदूषणकारी व्हीकल्स को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी या वोलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (**VVMP**) शुरू किया है।

- यह नीति रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रेपिंग फैसिलिटीज (**RVSF**) और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (**ATS**) के नेटवर्क के माध्यम से लागू की जाएगी।
- इस नीति में राज्य सरकारों को गैर-परिवहन व्हीकल्स के लिए 25% तक और परिवहन व्हीकल्स पर 15% तक मोटर व्हीकल टैक्स में छूट देने की सूचना दी गई है। अब, MoRTH ने स्कैप किए जाने वाले व्हीकल की किसी भी लंबित देनदारियों पर छूट जोड़ दी है।
- वाणिज्यिक और यात्री व्हीकल के निर्माता जमा प्रमाणपत्र (**स्कैपेज प्रमाणपत्र**) के विरुद्ध सीमित अवधि के लिए छूट देने पर सहमत हुए हैं।
- वर्तमान में, भारत में 17 राज्यों में 60 से अधिक RVSF और 12 राज्यों में पचहत्तर से अधिक ATS चालू हैं।

**47.** किस संगठन ने हाल ही में (अगस्त'24 में) डिजिलॉकर को अपने भर्ती पोर्टल के साथ एकीकृत किया है, जिससे उम्मीदवारों को अपने डिजिटल दस्तावेज़ लिंक करने की अनुमति मिलेगी?

- 1) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
- 2) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉर्मस एंड इंडस्ट्री
- 3) स्टाफ सिलेक्शन कमीशन
- 4) इंडियन रेलवे
- 5) इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन

उत्तर- **4) इंडियन रेलवे**

**स्पष्टीकरण:**

इंडियन रेलवे (**IR**) ने भर्ती प्रक्रिया की अवधि को **18-24** महीने से घटाकर **6** महीने से कम करने के लिए अपने भर्ती पोर्टल को **डिजिलॉकर** के साथ एकीकृत किया है।

- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स & सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (**MeitY**) की एक प्रमुख पहल **डिजिलॉकर**, एक डिजिटल दस्तावेज़ बटुआ है जो प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज़ों तक पहुँच प्रदान करता है।
- इस एकीकरण दस्तावेज़ सत्यापन को सुव्यवस्थित करेगा और नकली दस्तावेज़ सबमिशन की संभावना को कम करेगा।

#### **स्पष्टीकरण:**

नई दिल्ली (दिल्ली) स्थित RailTel कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (**RailTel**), जो रेल मंत्रालय (MoR) के तहत एक मिनी रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) है, को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (**ISO**) **14001:2015** प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, जो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (**EMS**) के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक है।

- i. यह प्रमाणन राष्ट्रीय दूरसंचार अवसंरचना, इंटरनेट, डिजिटल इंडिया और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के विकास का समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड दूरसंचार और मल्टीमीडिया नेटवर्क के RailTel के प्रशासन और प्रबंधन को शामिल करता है - ग्रामीण क्षेत्रों सहित भारत के सभी हिस्सों में मूल्यवर्धित सेवाओं को सक्षम बनाता है।
- ii. RailTel ने न केवल विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया है।

## **INTERNATIONAL AFFAIRS**

**1. हाल ही में (जुलाई'24 में) किस संगठन ने अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्फ इंडिविजुअल्स के कराधान को बढ़ाने के लिए अपना पहला संयुक्त मंत्रिस्तरीय घोषणा जारी किया है?**

- 1) G7 या ग्रुप ऑफ 7
- 2) शंघाई कॉऑपरेशन आर्गनाईजेशन (SCO)
- 3) यूनाइटेड नेशंस (UN)
- 4) वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन (WTO)
- 5) G20 या ग्रुप ऑफ 20

उत्तर- **5) G20 या ग्रुप ऑफ 20**

#### **स्पष्टीकरण:**

ग्रुप ऑफ ट्रेंटी (**G20**) के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकरों ने कराधान पर पहली बार संयुक्त मंत्रिस्तरीय घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग पर रियो डी जनेरियो **G20 मंत्रिस्तरीय घोषणा** जारी की, जो "अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्फ इंडिविजुअल्स" के प्रभावी कराधान के लिए प्रतिबद्ध है।

- इसे ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित **तीसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक राज्यपाल की बैठक** की विज्ञप्ति के दौरान अपनाया गया था। इस घोषणा में कर संप्रभुता का सम्मान करते हुए सहकारी जुड़ाव पर जोर दिया गया।
- **G20 की अध्यक्षता** करने वाले ब्राजील ने दुनिया के सबसे अमीर बिलियनेयर्स पर **2%** न्यूनतम कर का प्रस्ताव रखा, जिससे यह ब्राजील के रियो डी जनेरियो में 18 से 19 नवंबर, 2024 तक आगामी G20 शिखर सम्मेलन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया।

**2. हाल ही में (जुलाई'24 में) कौन सा देश कैरेबियन समुदाय (**CARICOM**) का सहयोगी सदस्य बन गया है?**

- 1) डोमिनिकन गणराज्य
- 2) जमैका
- 3) बेलीज
- 4) बेनिन
- 5) क्युरासाओ

उत्तर- **5) क्युरासाओ**

#### **स्पष्टीकरण:**

क्युरासाओ, विकासशील दुनिया में सबसे पुराना जीवित एकीकरण आंदोलन कैरीबियाई समुदाय (**CARICOM**) का छठा सहयोगी सदस्य बन गया है।

- समझौते पर CARICOM के अध्यक्ष डिकॉन मिशेल, (ग्रेनेडा के प्रधान मंत्री(PM)) और क्युरासाओ के PM गिलमार साइमन पिसास ने सेंट जॉर्ज, ग्रेनेडा में आयोजित सरकार के प्रमुखों के सम्मेलन की 47 वीं नियमित बैठक के उद्घाटन समारोह के दौरान हस्ताक्षर किए थे।

- इसके साथ ही, CARICOM में अब **15 पूर्ण सदस्य** देश और **6 सहयोगी सदस्य** शामिल हैं।
- 3. हाल ही में (अगस्त'24 में) कौन सा देश दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमान (UNC) में 18वें सदस्य राज्य के रूप में शामिल हुआ है?**
- भारत
  - फिलीपींस
  - जर्मनी
  - कनाडा
  - पोलैंड
- उत्तर- **3) जर्मनी**
- स्पष्टीकरण:**
- 2 अगस्त 2024 को, संघीय गणराज्य जर्मनी (**FRG**) आधिकारिक तौर पर दक्षिण कोरिया में सियोल के दक्षिण में प्योंगटेक में संयुक्त राज्य अमेरिका (**USA**) के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान (**UNC**) में शामिल हो गया।
- जर्मनी UNC का **18वाँ सदस्य** देश बन गया, यह एक ऐसा समूह है जो उत्तर कोरिया के साथ भारी किलेबंद सीमा की पुलिसिंग में मदद करता है और युद्ध की स्थिति में दक्षिण की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
  - यह **2013** में इटली के फिर से शामिल होने के बाद से पहला UNC विस्तार है।
  - UNC की स्थापना 7 जुलाई, 1950 को हुई थी, जब UN ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ उत्तर कोरिया के आक्रमण को मान्यता दी थी।
- 4. हाल ही में (अगस्त'24 में) स्काईट्रैक्स के विश्व एयरलाइन पुरस्कार 2024 में किस एयरलाइन को भारत/दक्षिण एशिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में नामित किया गया है?**
- एयर इंडिया
  - IndiGo
  - विस्तारा
  - स्पाइसजेट
  - Fly91
- उत्तर- **3) विस्तारा**
- स्पष्टीकरण:**
- स्काईट्रैक्स के विश्व एयरलाइन पुरस्कार **2024** ने भारतीय एयरलाइन **विस्तारा** (टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड) को भारत/दक्षिण एशिया **2024** में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में सम्मानित किया है। इसे 2021 से लगातार चौथी बार यह सम्मान मिला है। विस्तारा को विश्व की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन रैंकिंग में **16वें** और एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन रैंकिंग में **8वें** स्थान पर रखा गया है।
- कतर एयरवेज को 8वीं बार विश्व की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन चुना गया है। सिंगापुर एयरलाइंस, जो 2023 की सूची में शीर्ष पर थी, दूसरे स्थान पर है और उसके बाद **एमिरेट्स** तीसरे स्थान पर है।
  - विस्तारा ने 2024 विश्व एयरलाइन पुरस्कारों में कुल 8 पुरस्कार जीते हैं। इसने लगातार तीसरे वर्ष भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ बिजनेस क्लास एयरलाइन का पुरस्कार जीता है।
  - एयर इंडिया ने "एशिया में सबसे बेहतर एयरलाइन" का पुरस्कार जीता। इसने अपनी रैंकिंग 103वें (2023 में) से सुधार कर 90वें स्थान (2024 में) पर पहुंचाई है और शीर्ष 100 एयरलाइन सूची में प्रवेश किया है।
  - स्काईट्रैक्स लंदन, यूनाइटेड किंगडम स्थित एक कंसल्टेंसी है जो एयरलाइन और एयरपोर्ट समीक्षा वेबसाइट चलाती है। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

5. हाल ही में (अगस्त'24 में) किस फूलदार झाड़ी को असुरक्षित प्रजातियों की IUCN (अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ) की लाल सूची में शामिल किया गया है?

- 1) स्ट्रोबिलैथेस कुंथियाना
- 2) पेटोकोस्मिया अरुणाचलेंस
- 3) एम्बिलिका चक्रवर्ती
- 4) फ्लोगैकेथस सुधांसुशेखरी
- 5) मेलानोक्लामिस द्रौपदी

उत्तर- 1) स्ट्रोबिलैथेस कुंथियाना

**स्पष्टीकरण:**

नीलकुरिंजी (स्ट्रोबिलैथेस कुंथियाना), एक बैंगनी रंग की फूलदार झाड़ी जो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट (केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु) में पाई जाती है, को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की असुरक्षित प्रजातियों की लाल सूची में शामिल किया गया है।

- इस प्रजाति को IUCN मानदंड A2c के तहत "संकटग्रस्त" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो इसके अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण खतरे का संकेत देता है।
- यह दक्षिण-पश्चिम भारतीय पर्वतीय घास के मैदानों में नीलकुरिंजी का पहला वैश्विक मूल्यांकन है।
- नीलकुरिंजी, या कुरुंजी, या कुरिंजी जुलाई के मध्य से अक्टूबर के बीच, हर 12 साल में एक बार खिलता है।

6. किस देश ने हाल ही में (अगस्त'24 में) BRICS भागीदारों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) के सहयोग से औद्योगिक दक्षता केंद्र शुरू किया है?

- 1) संयुक्त अरब अमीरात
- 2) ऑस्ट्रेलिया
- 3) मॉरीशस
- 4) सऊदी अरब
- 5) श्रीलंका

उत्तर- 1) संयुक्त अरब अमीरात

**स्पष्टीकरण:**

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoIAT) ने औद्योगिक कौशल और क्षमताओं के विकास का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) के सहयोग से औद्योगिक दक्षता केंद्र शुरू करने के लिए BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) भागीदारों के साथ हाथ मिलाया है।

- i. रूस के निज़नी नोवगोरोड में 'स्ट्रेंगथेनिंग मल्टीलेटरलिस्म फॉर इक्विटाल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी' विषय पर रूस की अध्यक्षता में 8वीं BRICS उद्योग मंत्रियों की बैठक में यह घोषणा की गई।
- ii. BRICS सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के सतत विकास लक्ष्यों (SDG), विशेष रूप से उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे पर SDG 9 का समर्थन करने के लिए औद्योगिक नीति पर सहयोग करने की भी प्रतिबद्धता जताई।
- iii. घोषणा में नीति समन्वय, कार्मिक प्रशिक्षण और परियोजना विकास में PartNIR (पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रेवोलुशन) नवाचार केंद्र की भूमिका को मान्यता दी गई है।

7. अगस्त 2024 में, भारत ने \_\_\_\_\_ (देश) के डेल्फ़ट, नैनातिवु और अनलाईतिवु द्वीपों पर हाइब्रिड बिजली परियोजनाओं के लिए पहला भुगतान सौंपा।

- 1) मॉरीशस
- 2) श्रीलंका
- 3) फ़िजी
- 4) सेशल्स
- 5) मालदीव

उत्तर- 2) श्रीलंका

#### **स्पष्टीकरण:**

29 अगस्त, 2024 को, भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका के तीन द्वीपों (डेल्फिन, नैनातिवु और अनलाईतिवु द्वीप) पर हाइब्रिड बिजली परियोजनाओं के लिए पहला भुगतान श्रीलंका सरकार के बिजली और ऊर्जा मंत्री के सचिव डॉ. सुलक्षणा जयवर्धने और श्रीलंका सतत ऊर्जा प्राधिकरण (SLSEA) के अध्यक्ष रंजीत सेपाला को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित एक समारोह में सौंपा।

- यह नवीनतम विकास उच्चायुक्त झा द्वारा श्रीलंका भर में राजनीतिक जुड़ाव की एक श्रृंखला के बाद हुआ है।
- यह परियोजना भारत सरकार से **11 मिलियन अमेरिकी डॉलर** की अनुदान सहायता के तहत कार्यान्वित की जा रही है।

## **GOVT SCHEMES**

**1. जुलाई 2024 में, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्रालय ने 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर \_\_\_\_\_ तक की अधिकतम ऋण सीमा के साथ एक उन्नत 'मॉडल कौशल ऋण योजना' शुरू की।**

- 1) 8 लाख रुपये
- 2) 29.6 लाख रुपये
- 3) 7.5 लाख रुपये
- 4) 5 लाख रुपये
- 5) 17.4 लाख रुपये

उत्तर- **3) 7.5 लाख रुपये**

#### **स्पष्टीकरण:**

केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS) जयंत चौधरी (स्वतंत्र प्रभार/IC), कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्रालय (MSDE) ने कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए एक उन्नत 'मॉडल कौशल ऋण योजना' शुरू की है, जिसमें अधिकतम ऋण सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर **7.5 लाख रुपये** कर दी गई है।

- केंद्रीय बजट 2024-2025 में इसकी घोषणा की गई थी, संशोधित योजना का उद्देश्य सालाना **25,000 छात्रों** को लाभान्वित करना है।
- **उद्देश्य:** यह सुनिश्चित करके उस अंतर को पाटना कि महत्वाकांक्षी उम्मीदवारों को उनके कौशल प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिले।
- मॉडल कौशल ऋण योजना कौशल विकास के लिए श्रेय गारंटी निधि योजना (**CGFSSD**) पर आधारित है, जिसे **2015** में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।

**2. आंध्र प्रदेश (AP) सरकार द्वारा हाल ही में (जुलाई'24 में) कल्याण योजनाओं का नाम बदलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु सही है/हैं?**

- A) तल्लिकी वंदनम: इस योजना जिसे पहले 'जगत्रा अम्मा बोडी' के नाम से जाना जाता था, माताओं को उनके बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- B) डोक्का सीथम्मा मध्याह बड़ी बोजनम: यह योजना जिसे पहले 'जगत्रा गोरमुड्डा' के नाम से जाना जाता था, सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मध्याह भोजन योजना है।
- C) मन बड़ी-मन भविष्यक्तु: यह योजना जिसे पहले 'मन बदी नाडु नेडु' के नाम से जाना जाता था, स्कूल के जीर्णोद्धार पर केंद्रित है।

- 1) केवल A & B
- 2) केवल A & C
- 3) केवल B & C
- 4) केवल B
- 5) सभी A, B & C

उत्तर- **5) सभी A, B & C**

### **स्पष्टीकरण:**

**आंध्र प्रदेश (AP)** सरकार के शिक्षा विभाग ने AP के पूर्व मुख्यमंत्री (CM) येदुगुरी संदिती (YS) जगन मोहन रेड्डी के नाम पर रखी गई **6 छात्र कल्याण योजनाओं** का नाम बदलकर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिष्ठित हस्तियों के नाम पर रखा है।

- AP की सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (TDP) सरकार ने इन नामों को **सर्वपल्ली राधाकृष्णन**, अवूल पाकिर जैनुलाब्दीन (APJ) अब्दुल कलाम और डोक्का सीताम्मा सहित उल्लेखनीय व्यक्तित्वों के नाम से बदल दिया है।
- **तल्लिकी वंदनम:** इस योजना को पहले 'जगन्ना अम्मा वोडी' के नाम से जाना जाता था, यह माताओं को उनके बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्या मित्र:** इस योजना को पहले 'जगन्ना विद्या कनुका' के नाम से जाना जाता था, यह स्कूल बैग और किताबों सहित शिक्षा किट प्रदान करती है।
- **डोक्का सीताम्मा मध्याह बड़ी बोजनम:** यह योजना जिसे पहले 'जगन्ना गोरमुद्धा' के नाम से जाना जाता था, सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए एक मध्याह भोजन योजना है।
- **मन बड़ी-मन भविष्यक्तु:** यह योजना जिसे पहले 'मन बड़ी नाडु नेडु' के नाम से जाना जाता था, स्कूल के जीर्णोद्धार पर केंद्रित है।
- **बालिका रक्षा:** यह योजना जिसे पहले 'स्वेच्छा' के नाम से जाना जाता था, छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करती है।
- **अब्दुल कलाम प्रतिभा पुरस्कार:** इस योजना को पहले 'जगन्ना अनिमुथ्यालु' के नाम से जाना जाता था, जिसके तहत परीक्षा में अवल आने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को वित्तीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

**3. किस राज्य ने हाल ही में (अगस्त'24 में) 2026 तक बाल विवाह से निपटने के लिए 'मुख्य मंत्रीर निजीत मोइना असोनी (MMNMA)' नामक मासिक वित्तीय सहायता योजना शुरू की है?**

- 1) असम
  - 2) बिहार
  - 3) पश्चिम बंगाल
  - 4) तेलंगाना
  - 5) ओडिशा
- उत्तर-1) असम**

### **स्पष्टीकरण:**

असम के मुख्यमंत्री (CM) हिमंत बिस्वा सरमा ने असम के गुवाहाटी में लोक सेवा भवन में एक कार्यक्रम के दौरान **मुख्य मंत्रीर निजीत मोइना असोनी (MMNMA)** नामक मासिक वित्तीय सहायता योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य 2026 तक असम में बाल विवाह का मुकाबला करना है।

- इस योजना से पहले वर्ष में सरकारी खजाने पर लगभग 300 करोड़ रुपये और 5 वर्षों में **1500 करोड़** रुपये खर्च होने की उम्मीद है।
- इस योजना के तहत, 10 लाख लड़कियों (एक मिलियन) को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय अनुदान के साथ सहायता प्रदान की जाएगी।
- MMNMA योजना का उद्देश्य सरकारी और उद्यम शैक्षणिक संस्थानों (VEI) में उच्चतर माध्यमिक (HS) पहला वर्ष, स्नातक (पहला वर्ष) और स्नातकोत्तर (PG) पहला वर्ष में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाना है, जिसमें निजी शिक्षा संस्थानों (PEI) में नामांकित लड़कियां शामिल नहीं हैं।

**4. नवीन & नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने 'प्रधानमंत्री (PM)-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के तहत 'मॉडल सोलर विलेज' योजना के कार्यान्वयन के लिए कितना धन आवंटित किया?**

- 1) 750 करोड़ रुपये
- 2) 800 करोड़ रुपये

3) 850 करोड़ रुपये

4) 778 करोड़ रुपये

5) 700 करोड़ रुपये

उत्तर-2) 800 करोड़ रुपये

**स्पष्टीकरण:**

9 अगस्त 2024 को, नवीन & नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने 'प्रधानमंत्री (PM) सृजन सुरक्षा योजना' के तहत 'मॉडल सोलर विलेज' स्कीम को लागू करने के लिए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

- योजना घटक के तहत, सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने और ग्रामीण समुदायों को ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाने के लिए पूरे भारत में प्रति जिले एक मॉडल सोलर विलेज स्थापित करने पर जोर दिया गया है।
- **बजट आवंटन:** MNRE ने योजना के कार्यान्वयन के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें प्रति गांव 1 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- **गांव के लिए पात्रता मानदंड:** योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक गांव को प्रतिस्पर्धा मोड के तहत माना जाएगा। इसके अलावा, गांव 5,000 (या विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2,000) से अधिक आबादी वाला राजस्व गांव होना चाहिए।

5. अगस्त 2024 में, हिमाचल प्रदेश (HP) सरकार ने \_\_\_\_\_ को बढ़ावा देने के लिए 'HIM-UNNATI' पहल शुरू की।

1) सड़क सुरक्षा

2) प्राकृतिक खेती

3) साइबर सुरक्षा

4) ग्रामीण स्वच्छता

5) कौशल विकास

उत्तर- 2) प्राकृतिक खेती

**स्पष्टीकरण:**

हिमाचल प्रदेश (HP) सरकार ने राज्य भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल 'HIM-UNNATI' शुरू की है। यह योजना राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के तीसरे चरण का प्रतिनिधित्व करती है, जो प्राकृतिक खेती के तरीकों को और प्रोत्साहित करती है।

- HP सरकार ने HIM-UNNATI योजना के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह योजना 32,149 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर पहले से ही रसायन मुक्त खेती कर रहे लगभग 1.92 लाख किसानों के प्रयासों को बढ़ावा देगी।
- यह प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर कलस्टर-आधारित विकास मॉडल के माध्यम से कृषि क्षेत्र को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

6. किस राज्य ने हाल ही में (अगस्त '24 में) युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान (MYUVA) योजना शुरू की है?

1) हरियाणा

2) राजस्थान

3) उत्तर प्रदेश

4) महाराष्ट्र

5) बिहार

उत्तर-3) उत्तर प्रदेश

### स्पष्टीकरण:

15 अगस्त 2024 (78वें स्वतंत्रता दिवस) पर, उत्तर प्रदेश (UP) के मुख्यमंत्री (CM) योगी आदित्यनाथ ने UP के युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान (MYUVA) योजना शुरू करने की घोषणा की है।

- MYUVA योजना का उद्देश्य 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके हर साल एक लाख युवा उद्यमी तैयार करना है।
- सरकार ने इस पहल का समर्थन करने के लिए 2024-25 के बजट में 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- यह स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और दस लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के गठन को प्रोत्साहित करके पूरे UP में शिक्षित और कुशल युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है।

**7. किस राज्य ने हाल ही में (अगस्त '24 में) महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना" (JMMSY) शुरू की है?**

1) पंजाब

2) राजस्थान

3) उत्तर प्रदेश

4) बिहार

5) झारखंड

उत्तर- 5) झारखंड

### स्पष्टीकरण:

18 अगस्त 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री (CM) हेमंत सोरेन ने झारखंड के पाकुड़ में राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए "झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना" (JMMSY) शुरू की।

- उन्होंने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से 57,120 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 1000 रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित की।
- जिन महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है और उनकी आयु 21 से 50 वर्ष है, उन्हें प्रति माह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- महाराष्ट्र सरकार ने 'नारी शक्ति धूत' नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए इस योजना के लिए पात्र महिलाएँ आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
- झारखंड सरकार ने भी एक स्वास्थ्य सेवा योजना 'मुख्यमंत्री आबकारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' शुरू की है, जिसके तहत लाभार्थियों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 15 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।

**8. किस राज्य सरकार ने हाल ही में (अगस्त '24 में) सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना (MBPAY) शुरू की है?**

1) उत्तराखण्ड

2) गोवा

3) हिमाचल प्रदेश

4) कर्नाटक

5) बिहार

उत्तर- 3) हिमाचल प्रदेश

### स्पष्टीकरण:

18 अगस्त 2024 को, हिमाचल प्रदेश (HP) के मुख्यमंत्री (CM) सुखविंदर सिंह सुखू ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना (MBPAY) शुरू की।

i. राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष (FY25) में इस योजना के लिए अतिरिक्त 12.75 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

ii. यह योजना 5.34 लाख स्कूली बच्चों को पोषण प्रदान करती है, जो मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

**9. किस राज्य ने हाल ही में (अगस्त'24 में) महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए सुभद्रा योजना शुरू की है?**

1)उत्तर प्रदेश

2)गुजरात

3)ओडिशा

4)बिहार

5)অসম

उत्तर- 3)ओडिशा

**स्पष्टीकरण:**

ओडिशा के मुख्यमंत्री (CM) मोहन चरण माझी ने सुभद्रा योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की घोषणा की है, जिसके तहत ओडिशा में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सालाना **10,000 रुपये** की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

- इस योजना को मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) से वित्तीय वर्ष 2028-29 (FY29) तक लागू करने के लिए **55,825 करोड़ रुपये** के आवंटित बजट के साथ मंजूरी दी थी।
- 21 से 60 वर्ष** की आयु की महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए पात्र होंगी।
- राखी पूर्णिमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) पर 5000 रुपये की दो किस्तों में प्रत्येक वर्ष कुल 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार पांच वर्षों में कुल 50,000 रुपये प्राप्त होंगे।
- लाभार्थी को 'सुभद्रा' डेबिट कार्ड भी मिलेगा।
- इस योजना की निगरानी के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सुभद्रा समिति की स्थापना की जाएगी।

**10. किस राज्य ने हाल ही में (अगस्त'24 में) विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना' शुरू की है?**

1)महाराष्ट्र

2)हिमाचल प्रदेश

3)तेलंगाना

4)बिहार

5)उत्तर प्रदेश

उत्तर- 2)हिमाचल प्रदेश

**स्पष्टीकरण:**

हिमाचल प्रदेश (HP) सरकार ने विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता-पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण में सहायता करने के लिए **वित्तीय सहायता** प्रदान करने हेतु **53.21 करोड़ रुपये** के वार्षिक आवंटन के साथ 'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना' शुरू की है।

- इस योजना का लक्ष्य दो विशिष्ट आयु समूहों की सहायता करना है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों, पात्र महिलाओं और विकलांग माता-पिता को उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए **1000 रुपये** का मासिक अनुदान मिलेगा।
- यह योजना बच्चों को अंडरग्रेजुएट (UG), पोस्टग्रेजुएट (PG), डिप्लोमा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, जिसमें पाठ्यक्रम शुल्क और छात्रावास व्यय शामिल हैं।
- इस योजना का लाभ पात्र बच्चों और महिला परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय **1 लाख रुपये** से अधिक नहीं है।

**11. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष जल जीवन मिशन (JJM) शुरू किया था?**

1)2015

2)2020

3)2019

4) 2016

5) 2018

उत्तर- 3) 2019

#### स्पष्टीकरण:

**15 अगस्त 2024 को जल जीवन मिशन (JJM):** हर घर जल की 5वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, भारत सरकार की प्रमुख योजना है जिसे राज्यों के साथ साझेदारी में पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS), जल शक्ति मंत्रालय (MoJS) द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

- जल जीवन मिशन की शुरुआत भारत के प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने **15 अगस्त 2019** (भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस) को नई दिल्ली, दिल्ली के लाल किले में की थी।
- इस योजना का लक्ष्य 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार (HH) को नल का जल उपलब्ध कराना है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि JJM पानी इकट्ठा करने में लगने वाले समय को कम करके, मुख्य रूप से महिलाओं के लिए, प्रतिदिन 5.5 करोड़ घंटे से अधिक समय बचाएगा।
- WHO का अनुमान है कि भारत भर में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने से डायरिया से होने वाली लगभग 400,000 मौतों को रोका जा सकता है और 14 मिलियन विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (DALY) बचाए जा सकते हैं।
- 12 अगस्त 2024 तक, JJM ने 11.82 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को सफलतापूर्वक नल जल कनेक्शन प्रदान किया है। कुल कवरेज बढ़कर 15.07 करोड़ परिवार हो गया है, जो भारत के सभी ग्रामीण परिवारों का **77.98%** है।
- 14 अगस्त 2024 तक 188 जिलों, 1,838 ब्लॉकों, 1,09,996 ग्राम पंचायतों और 2,33,209 गांवों ने 'हर घर जल' का दर्जा हासिल करने की सूचना दी है। आगे पढ़ने के लिए यहाँ क्लीक करें

**12. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु 'सही' है/हैं?**

A) प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।

B) डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख रुपये के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर के साथ रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किया गया है।

C) 14 अगस्त, 2024 तक PMJDY ने 53.13 करोड़ लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया है।

1) केवल A & B

2) केवल B & C

3) केवल A & C

4) केवल A

5) सभी A, B & C

उत्तर- 5) सभी A, B & C

#### स्पष्टीकरण:

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन, जिसे 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, ने सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के **10 वर्ष** (दशक) पूरे कर लिए हैं।

- इसे वित्तीय सेवा विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय (MoF) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- PMJDY वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (FI) है।
- PMJDY का नारा "मेरा खाता, भाग्य विधाता" (माय अकाउंट, फार्चून मेकर) है।
- PMJDY खाता खोलने के लिए कोई आयु प्रतिबंध नहीं है और खाते शून्य शेष राशि के साथ खोले जाते हैं।

- डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख रुपये के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर के साथ रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है।
- पात्र खाताधारकों को **10,000 रुपये** तक की ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा है।
- **व्यापक वित्तीय समावेशन:** PMJDY ने 14 अगस्त, 2024 तक 53.13 करोड़ लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया है, जिसमें **55.6%** (29.56 करोड़) जन-धन खाताधारक महिलाएँ हैं और 66.6% (35.37 करोड़) खाते ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।
- **जमा वृद्धि:** PMJDY खातों में कुल जमा राशि **2,31,236 करोड़ रुपये** तक पहुंच गई है, जो 2015 से 15 गुना वृद्धि को दर्शाती है। [अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें](#)

**13. किस संगठन ने हाल ही में (अगस्त'24 में) SPICED - "सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव, एंड कोलाबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट" नामक एक योजना शुरू की है?**

- 1)भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
- 2)भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
- 3)कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
- 4)भारतीय खाद्य और कृषि कक्ष
- 5)भारतीय मसाला बोर्ड

उत्तर- 5)भारतीय मसाला बोर्ड

**स्पष्टीकरण:**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (**MoCI**) के तहत भारतीय मसाला बोर्ड ने **422.30 करोड़ रुपये** के बजट के साथ **SPICED - "सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव, एंड कोलाबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट"** नामक एक परिवर्तनकारी योजना शुरू की है।

- SPICED के तहत शुरू किए गए कार्यक्रम **15वें वित्त आयोग चक्र (FY2025-26 तक)** की शेष अवधि के दौरान लागू किए जाएंगे।
- **उद्देश्य:** मसाला निर्यात को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देना, उत्पादकता बढ़ाना और मसालों की कटाई के बाद की गुणवत्ता को उन्नत करना।
- यह मिशन वैल्यू एडिशन, मिशन क्लीन एंड सेफ स्पाइस, GI (भौगोलिक संकेत) मसालों को बढ़ावा देने जैसे उप-घटकों को पेश करके मसाला क्षेत्र में मूल्यवर्धन और नवाचार और स्थिरता की सुविधा प्रदान करेगा।

**14. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्स्टाइल्स की 'ग्रांट फॉर रिसर्च & एंट्रेप्रेनरशिप अक्रॉस अस्पैरिंग इन्नोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्स्टाइल्स (GREAT)' योजना के तहत प्रत्येक स्वीकृत स्टार्ट-अप को मिलने वाले अनुदान की अनुमानित राशि क्या है?**

- 1)20 लाख रुपये
- 2)60 लाख रुपये
- 3)30 लाख रुपये
- 4)80 लाख रुपये
- 5)50 लाख रुपये

उत्तर- 5)50 लाख रुपये

**स्पष्टीकरण:**

मिनिस्ट्री ऑफ टेक्स्टाइल्स (**MoT**) की सचिव रचना शाह ने उद्योग भवन, नई दिल्ली में नेशनल टेक्निकल टेक्स्टाइल्स मिशन (**NTTM**) के तहत **8वीं** अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति (**EPC**) की बैठक की अध्यक्षता की। समिति ने 'ग्रांट फॉर रिसर्च & एंट्रेप्रेनरशिप अक्रॉस अस्पैरिंग इन्नोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्स्टाइल्स (GREAT)' योजना के तहत लगभग **50 लाख रुपये** के अनुदान के साथ 4 स्टार्ट-अप को मंजूरी दी है।

- समिति ने 'जनरल गाइडलाइन्स फॉर एनेबलिंग ऑफ एकाडेमिक इंस्टीट्यूट्स इन टेक्निकल टेक्स्टाइल्स' के तहत टेक्निकल टेक्स्टाइल्स (TT) में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NIT) सहित 5 शिक्षा संस्थानों को लगभग 20 करोड़ रुपये के अनुदान को भी मंजूरी दी है।
- स्वीकृत स्टार्टअप कंपोजिट, स्टेनेबल टेक्स्टाइल्स और स्मार्ट टेक्स्टाइल्स के प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों पर केंद्रित हैं।

## VISITS

1. जुलाई 2024 में, भारत ने वियतनाम के प्रधान मंत्री (PM) फाम मिन्ह चिन्ह की भारतीय यात्रा के दौरान अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वियतनाम को कुल \_\_\_\_\_ की दो लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) प्रदान की।

- 1) 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर
- 2) 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर
- 3) 135 मिलियन अमेरिकी डॉलर
- 4) 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर
- 5) 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर

उत्तर- 4) 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर

### स्पष्टीकरण:

वियतनाम के प्रधानमंत्री(PM) ने भारत H.E फाम मिन्ह चिन्ह के PM नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक भारत की राजकीय यात्रा की, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना और सहयोग को बढ़ाना है।

- अपनी बढ़ती रणनीतिक साझेदारी के संकेत के रूप में, भारत ने वियतनाम को देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दो ऋण रेखाएँ (LoC) प्रदान की हैं।
- भारत और वियतनाम ने एक नई कार्ययोजना पर सहमति जताई, जिसे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए अगले पांच वर्षों (2024-2028) में लागू किया जाएगा।
- भारत और वियतनाम ने गुजरात के लोथल में नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज काम्प्लेक्स (NMHC) के साथ समुद्री इतिहास को संरक्षित करने के लिए हाथ मिलाया।
- PM मोदी और वियतनाम के PM फाम मिन्ह चिन्ह ने वियतनाम के न्हा ट्रांग में दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

2. अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू की फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु 'सही' है/हैं?

- A) राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया।
- B) भारत और फिजी ने दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- C) राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू को ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया
- 1) केवल A & B
  - 2) केवल A & C
  - 3) केवल B & C
  - 4) केवल A
  - 5) सभी A, B & C
- उत्तर- 2) केवल A & C

### स्पष्टीकरण:

भारत की राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू 5 अगस्त से 10 अगस्त 2024 तक फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की 3-राष्ट्र यात्रा पर थीं।

- राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया।
- भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- न्यूजीलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की पुष्टि की है जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास के लिए बढ़े हुए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करता है।
- राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया, जहाँ भारत को वर्ष 2024 के लिए 'कंट्री होनर' दिया गया।
- राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के डिली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति होर्टा द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। [अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें](#)

3. किस देश ने हाल ही में (अगस्त'24 को) यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) शुरू करने के लिए भारत सरकार के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए?

- आइवरी कोस्ट
- अज़रबैजान
- मालदीव
- पैराग्वे
- तिमोर लेस्ते

उत्तर- 3) मालदीव

### स्पष्टीकरण:

केंद्रीय मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर, विदेश मंत्रालय (MEA) ने 9 से 11 अगस्त, 2024 तक 3 दिनों के लिए मालदीव का आधिकारिक दौरा किया, जो कि हाल ही में जून 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति H.E. डॉ. मोहम्मद मुइज़्ज़ की भारत यात्रा के बाद भारत-मालदीव संबंधों को मजबूत करने और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए था।

- भारत और मालदीव ने मालदीव में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- उन्होंने मालदीव में जल और स्वच्छता परियोजना, अदू रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, अदू शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट और 6 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDP) का उद्घाटन किया।
- उन्होंने भारत में अतिरिक्त 1000 मालदीव के सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण पर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए और मालदीव में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की शुरूआत की।
- उन्होंने भारत द्वारा सहायता प्राप्त ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) साइट की समीक्षा की, जो माले को विलिंगिली, गुलहिफाल्हू और थिलाफुशी के निकटवर्ती द्वीपों से जोड़ेगी। [अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें](#)

4. मलेशियाई प्रधान मंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम की 19 से 21 अगस्त 2024 तक की भारतीय यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु 'सही' है/हैं?

- A) आपसी सहयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण (IFSCA) और लाबुआन वित्तीय सेवा प्राधिकरण (LFSA), मलेशिया के बीच MoU पर हस्ताक्षर किए गए।
- B) मलेशिया ने अपने संस्थापक सदस्य के रूप में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) में शामिल होने का फैसला किया है।
- C) PM नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत मलेशिया के नेशनल पेमेंट नेटवर्क, PayU के साथ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को एकीकृत करने की योजना बना रहा है।

1) केवल A & B

2) केवल B & C

3) केवल A & C

4) केवल B

5) सभी A, B & C

उत्तर- 1) केवल A & B

#### स्पष्टीकरण:

मलेशिया के प्रधानमंत्री (PM) H.E. दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम भारत के प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 19 अगस्त से 21 अगस्त 2024 तक भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर थे, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया जा सके और सहयोग बढ़ाया जा सके।

- 2022 में मलेशिया के PM बनने के बाद से यह मलेशियाई PM अनवर बिन इब्राहिम की भारत और दक्षिण एशिया क्षेत्र की पहली यात्रा है।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 19.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- मलेशिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) में इसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का फैसला किया है।
- भारत सरकार (GoI) ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) के माध्यम से मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन (MT) गैर-बासमती सफेद चावल के विशेष आवंटन की अनुमति दी है।
- मलेशियाई PM अनवर बिन इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद, PM नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत मलेशिया के नेशनल पेमेंट नेटवर्क, पेनेट के साथ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को एकीकृत करने की योजना बना रहा है।
- GoI और मलेशिया सरकार (GoM) ने सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों (MoU) और समझौतों जैसे: श्रमिकों की भर्ती, रोजगार और प्रत्यावर्तन; आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियाँ; डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ; संस्कृति, कला और विरासत, आदि पर हस्ताक्षर किए हैं।
- आपसी सहयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण (IFSCA) और लाबुआन वित्तीय सेवा प्राधिकरण (LFSA), मलेशिया के बीच MoU पर हस्ताक्षर किए गए।

5. अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से बिंदु 'सही' है/हैं?

A) भारत और पोलैंड ने भारत-पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों को "स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक पांच साल की जॉइंट एक्शन प्लान फॉर 2024-2028" के रूप में उन्नत करने का निर्णय लिया है।

B) भारत और यूक्रेन आर्थिक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग (JCEC) का उपयोग करने के लिए सहमत हुए, जिसे 2024 के अंत तक आयोजित किया जाना है।

C) PM मोदी ने यूक्रेन सरकार को चार भारत हेल्थ इनिशिएटिव्स फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री (BHISHM क्यूब्स) प्रस्तुत की।

1) केवल A & B

2) केवल A & C

3) केवल B & C

4) केवल A

5) सभी A, B & C

उत्तर- 2) केवल A & C

#### स्पष्टीकरण:

भारत के प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के PM डोनाल्ड ट्रस्क के निमंत्रण पर 21 से 22 अगस्त 2024 तक पोलैंड का दौरा किया।

उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन का भी दौरा किया।

- यह 1979 में मोरारजी देसाई के बाद पिछले 45 वर्षों में पोलैंड में किसी भारतीय PM की पहली यात्रा है।

- मोदी की यूक्रेन यात्रा 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से किसी भारतीय PM की पहली यूक्रेन यात्रा है।
- भारत और पोलैंड ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत-पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों को "स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप" के रूप में उन्नत करने का निर्णय लिया है।
- स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लागू करने के लिए, भारत और पोलैंड दोनों ने पांच साल की **जॉइंट एक्शन प्लान फॉर 2024-2028** पर सहमति व्यक्त की है।
- भारतीय PM नरेंद्र मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कृषि, चिकित्सा, संस्कृति & मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करते हुए चार प्रमुख समझौतों को औपचारिक रूप दिया है।
- PM मोदी ने यूक्रेन सरकार को चार भारत हेल्प इनिशिएटिव्स फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री (BHISHM क्यूब्स) प्रस्तुत की। [अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें](#)

**6. 25 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र और राजस्थान यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?**

- A) PM मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए और सम्मानित किया।
- B) उन्होंने 2,500 करोड़ रुपये का एक रिवॉल्विंग फंड यानी सामुदायिक निवेश कोष भी जारी किया, जिसका उद्देश्य 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ पहुँचाना है।
- C) PM नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्वर्ण जयंती (50 वर्ष) के समापन समारोह को संबोधित किया।

- 1)केवल A & B
- 2)केवल B & C
- 3)केवल A & C
- 4)केवल A
- 5)सभी A, B & C

उत्तर- 1)केवल A & B

#### स्पष्टीकरण:

प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी 25 अगस्त, 2024 को महाराष्ट्र और राजस्थान की यात्रा पर हैं।

- i.PM मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने PM मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान लखपति का मुकाम हासिल करने वाली **11 लाख** नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए और सम्मानित किया।
- ii.उन्होंने 2,500 करोड़ रुपये का एक रिवॉल्विंग फंड यानी सामुदायिक निवेश कोष भी जारी किया, जिसका उद्देश्य 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ पहुँचाना है।
- iii.PM नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जुबली (**75 वर्ष**) के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्हें समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। [अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें](#)

**7. भारत हाल ही में (अगस्त'24 में) \_\_\_\_\_ (देश) का 18वां आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था (SOSA) भागीदार बन गया है।**

- 1)संयुक्त राज्य अमेरिका
  - 2)फ्रांस
  - 3)सिंगापुर
  - 4)वियतनाम
  - 5)बेलारूस
- उत्तर- 1)संयुक्त राज्य अमेरिका

#### **स्पष्टीकरण:**

रक्षा मंत्रालय (**MoD**) के केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के निमंत्रण पर 23 से 26 अगस्त 2024 तक वाशिंगटन D.C., संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की **आधिकारिक यात्रा** पर थे।

- राजनाथ सिंह और लॉयड ऑस्टिन ने भारत और US के बीच 22 अगस्त 2024 को हस्ताक्षरित द्विपक्षीय, गैर-बाध्यकारी आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था (SOSA) के समापन पर भी प्रकाश डाला। भारत USA का 18वां SOSA भागीदार है।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वाशिंगटन D.C., USA यात्रा के दौरान भारत और USA ने दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। संपर्क अधिकारियों की तैनाती के लिए भारत और USA के बीच **समझौता ज्ञापन (MoA)** पर हस्ताक्षर किए गए।
- USA ने भारत को 52.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत पर सोनोबॉय और संबंधित गियर की विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य भारत की एंटी-सबमरीन वारफेर तक्षमताओं को बढ़ाना, विशेष रूप से इसके MH-60R हेलीकॉप्टरों के लिए है। मुख्य ठेकेदार **स्पार्टन कॉरपोरेशन** और अंडरसी सेंसर सिस्टम्स इंक हैं।
- भारत और USA ने तेजस MK-2 विमान के लिए GE F-414 इंजन और स्ट्राइकर बख्तरबंद पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों सहित सह-उत्पादन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
- MoD राजनाथ सिंह ने टेनेसी के मेम्फिस में विलियम B. मॉर्गन लार्ज कैविटेशन चैनल (LCC) का दौरा किया, जहां USA नौसेना पनडुब्बियों और नौसेना सतह जहाजों का परीक्षण करती है। [अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें](#)

## BANKING AND FINANCE

1. किस बैंक ने हाल ही में (जुलाई'24 में) भारत के 8 राज्यों के 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार (GoI) के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?

- 1) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
  - 2) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
  - 3) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)
  - 4) एशियाई विकास बैंक (ADB)
  - 5) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA)
- उत्तर- 4) एशियाई विकास बैंक (ADB)

#### **स्पष्टीकरण:**

भारत सरकार (GoI) ने भारत के 8 राज्यों के 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- यह ऋण समझौता स्वच्छ भारत मिशन (SBM) 2.0: भारतीय शहरों में व्यापक नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम का हिस्सा है।
- यह ऋण व्यवस्था स्वच्छ भारत (क्लीन इंडिया) मिशन-अर्बन 2.0 के उद्देश्यों का समर्थन करेगी, जो GoI द्वारा संचालित एक पहल है जिसका उद्देश्य 2026 तक सभी भारतीय शहरों को कचरा मुक्त बनाना है, जिसमें अपशिष्ट पृथक्करण, संग्रहण और निपटान सहित स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जाएगा।

**2. किस संगठन ने मार्च 2024 के अंत में डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (RBI-DPI) में 445.5 की वृद्धि दर्ज की, जो साल-दर-साल 12.6% की वृद्धि को दर्शाता है?**

- 1) रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)
- 2) मिराए एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- 3) NSE इंडेक्स लिमिटेड
- 4) MSCI इंक
- 5) इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (IFSCA)

उत्तर- **1) रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)**

**स्पष्टीकरण:**

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (**RBI**) का डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (**RBI-DPI**) मार्च 2024 के अंत में बढ़कर **445.5** हो गया, जो सभी मापदंडों पर मार्च 2023 की तुलना में साल-दर-साल (Y-o-Y) **12.6%** की वृद्धि दर्शाता है। सितंबर 2023 में यह **418.77** और मार्च 2023 में **395.57** था।

- RBI-DPI पूरे भारत में ऑनलाइन लेनदेन को अपनाने और उसकी सीमा को मापता है।
- वर्तमान में डिजिटल भुगतान अपनाने में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है।
- RBI ने पूरे भारत में भुगतान के डिजिटलीकरण का अनुमान लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार वर्ष मानते हुए जनवरी 2021 में RBI-DPI की शुरुआत की।

**3. किस संगठन/बैंक ने हाल ही में (जुलाई'24 में) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को ऋण की सुविधा के लिए C2treds और UGRO कैपिटल के साथ सह-उधार साझेदारी की है?**

- 1) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
- 2) रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (RXIL)
- 3) स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI)
- 4) नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NSIC)

उत्तर- **3) स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI)**

**स्पष्टीकरण:**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (**SIDBI**) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (**MSME**) क्षेत्र को ऋण की सुविधा के लिए **C2treds**, **C2FO**, दुनिया के ऑन-डिमांड वर्किंग कैपिटल प्लेटफॉर्म और **UGRO** कैपिटल, एक डेटा टेक्नोलॉजी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (**NBFC**) की एक रणनीतिक पहल के साथ सह-उधार साझेदारी की है।

- ये साझेदारियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के सह-उधार ढांचे के तहत स्थापित की गई हैं, जिसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने को बढ़ावा देने के लिए बैंकों और NBFC की ताकत का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **SIDBI** ने **C2treds** को शामिल किया है, जो **C2FO** द्वारा **RBI** द्वारा अनुमोदित टेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (**TReDS**) प्लेटफॉर्म है। इस सहयोग का उद्देश्य MSME के लिए प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर तरलता में सुधार करना है।

**4. किस संगठन ने हाल ही में (जुलाई'24 में) रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए आसान वित्तपोषण की सुविधा के लिए बैंक ऑफ इंडिया (BOI) के साथ सहयोग किया है?**

- 1) एनजी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL)
- 2) अदानी ग्रीन एनजी लिमिटेड (AGEL)
- 3) एम्पइन एनजी टांजिशन प्राइवेट लिमिटेड
- 4) JSW नियो एनजी लिमिटेड (JSW नियो)
- 5) टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड (TPSSL)

उत्तर- **5) टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड (TPSSL)**

### **स्पष्टीकरण:**

26 जुलाई 2024 को, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (**TPREL**) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड (**TPSSL**) ने घोषणा की कि उसने छत पर सोलर लगाने और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए आसान वित्तपोषण की सुविधा के लिए बैंक ऑफ इंडिया (**BOI**), भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (**PSB**) के साथ सहयोग किया है।

- 3 KW तक की स्थापना के लिए: प्रधानमंत्री (PM) सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, आवासीय ग्राहक 5% की मार्जिन मनी आवश्यकता के साथ 7.10% की वार्षिक ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं।
- KW से 10 KW तक की स्थापना के लिए: पात्र आवेदक 5% मार्जिन मनी आवश्यकता के साथ 6 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। ब्याज दर 8.3% से 10.25% प्रति वर्ष तक है, और ये भी बिना किसी जमानत के हैं और इनकी अवधि 10 वर्ष तक है।
- UDYAM-पंजीकृत सभी MSME ग्राहक 9.35% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 30 करोड़ रुपये तक का ऋण ले सकते हैं, जिसमें 15% मार्जिन मनी की आवश्यकता है।

### **5. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस (RCF) फॉर 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है?**

A) भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 10% है और 2026 तक इसके दोगुना होकर 20% होने की उम्मीद है।

B) पिछले सात वर्षों (2017-18 और 2023-24 के बीच) में डिजिटल भुगतान में मात्रा के लिहाज से 40% और मूल्य के लिहाज से 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) देखी गई है।

C) RCF 2023-24 रिपोर्ट का विषय "इंडियास डिजिटल रेवोलुशन" है।

1) केवल A & B

2) केवल A & C

3) केवल B & C

4) केवल B

5) सभी A, B & C

उत्तर- 2) केवल A & C

### **स्पष्टीकरण:**

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 29 जुलाई 2024 को **रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस (RCF) फॉर 2023-24** जारी की है। रिपोर्ट उन चुनौतियों पर प्रकाश डालती है जो एक अर्थव्यवस्था का सामना करना पड़ता है।

- RCF 2023-24 रिपोर्ट के लिए थीम "इंडियास डिजिटल रेवोलुशन" है।

i. RCF 2023-24 के अनुसार, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 10% पर है और 2026 तक 20% से दोगुना होने की उम्मीद है।

ii. डिजिटल भुगतानों ने पिछले सात वर्षों में (2017-18 और 2023-24 के बीच) में मूल्य के संदर्भ में 50% और 10% की एक मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) देखा है।

iii. भारत के दुनिया का प्रमुख श्रम आपूर्तिकर्ता होने की उम्मीद है, जो प्रेषण को 2023 में 115 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2029 में लगभग 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा देगा। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

### **6. जुलाई 2024 में, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने \_\_\_\_\_ पर भारत की पहली वेबसाइट फॉर पैसिव फंड लॉन्च की।**

1) इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड

2) इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFSC लिमिटेड

3) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

4) BSE लिमिटेड

5) रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

### उत्तर- 3) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

#### स्पष्टीकरण:

30 जुलाई 2024 को, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (**SEBI**) की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (**NSE**) में भारत की पहली वेबसाइट फॉर पैसिव फंड लॉन्च की, ताकि खुदरा निवेशकों के लिए एक व्यापक मंच की सुविधा मिल सके और उन्हें आसानी से जानकारी तक पहुँचने और भारतीय निष्क्रिय उद्योग को समझने में सक्षम बनाया जा सके।

- पैसिव फंड के लिए वेबसाइट लॉन्च करने के अलावा, उन्होंने पूँजी बाजारों पर “इंडियन कैपिटल मार्केट्स: ट्रांसफॉर्मिटिव शिप्ट्स अचीव थ्रू टेक्नोलॉजी एंड रिफॉर्म्स” शीर्षक से रिपोर्ट का भी अनावरण किया।
- रिपोर्ट **NSE डेटा एनालिटिक्स** द्वारा विकसित की गई है, जिसमें प्रमुख तकनीकी प्रगति और नियामक सुधारों को शामिल किया गया है, जिन्होंने भारतीय पूँजी बाजारों को प्रभावित किया है। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

### 7. हाल ही में (जुलाई '24 में) किस कंपनी को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (**IRDAI**) से समग्र इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है?

- मुमुक्षु माइक्रोफिन लिमिटेड
- कोवरज़ी
- महिंद्रा & महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
- InsuranceDekho
- पैसाबाज़ार

### उत्तर- 4) InsuranceDekho

#### स्पष्टीकरण:

गुरुग्राम (हरियाणा) स्थित इंश्योरेंस बाज़ार, InsuranceDekho को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (**IRDAI**) से कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है।

- यह लाइसेंस फर्म को अपनी मौजूदा इंश्योरेंस ब्रोकिंग पेशकशों के साथ-साथ रीइंश्योरेंस ब्रोकिंग सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति देता है।
- रीइंश्योरेंस ब्रोकिंग क्षेत्र में प्रवेश करके, InsuranceDekho का लक्ष्य गहन वितरण नेटवर्क, डिजिटलीकरण, नई उत्पाद लाइनों में विविधीकरण और इंश्योरेंसभागीदारों के लिए समर्थन के माध्यम से भारत में इंश्योरेंस पैठ को बढ़ाना है।

### 8. किस बैंक ने हाल ही में (अगस्त '24 में) **GOQii** के साथ साझेदारी में संपर्क रहित भुगतान के लिए स्मार्ट वाइटल प्लस स्मार्टवॉच लॉन्च की है?

- ICICI बैंक
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- कोटक महिंद्रा बैंक
- HDFC बैंक
- एक्सिस बैंक

### उत्तर- 3) कोटक महिंद्रा बैंक

#### स्पष्टीकरण:

1 अगस्त 2024 को, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (**KMBL**), एक प्रमुख भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक, ने स्मार्ट-टेक-इनेबल्ड प्रिवेटिव हेल्पकेयर प्लेटफॉर्म **GOQii** के साथ साझेदारी में, “कोटक-**GOQii** स्मार्ट वाइटल प्लस स्मार्टवॉच” लॉन्च करने की घोषणा की है, जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (**NPCI**) द्वारा संचालित एक पहनने योग्य और संपर्क रहित RuPay चलते-चलते भुगतान समाधान है।

- कोटक-**GOQii** स्मार्ट वाइटल प्लस अपने ग्राहकों को संपर्क रहित भुगतान करने में सक्षम बनाएगा और साथ ही उन्हें कुछ स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी करने में भी सक्षम बनाएगा।
- इस पहनने योग्य उपकरण की शुरुआती कीमत **3,499 रुपये** है।

- इस स्मार्टवॉच को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (**MoHFW**) के तहत नई दिल्ली (दिल्ली) स्थित केंद्रीय औषधि और मानक नियंत्रण संगठन (**CDSO**) द्वारा एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मान्यता दी गई है।

**9. हाल ही में (जुलाई'24 में) कौन सा बैंक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (**UPI**) और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (**NMC**) दोनों सुविधाओं के साथ RuPay क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है?**

- 1) HDFC बैंक
- 2) RBL बैंक
- 3) एक्सिस बैंक
- 4) ICICI बैंक
- 5) YES बैंक

उत्तर- **2)RBL बैंक**

**स्पष्टीकरण:**

एक अग्रणी भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक, **RBL बैंक** (जिसे पहले रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (**UPI**) और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (**NMC**) सुविधाओं को एकीकृत करते हुए एक नया **RuPay क्रेडिट कार्ड** लॉन्च किया है।

- इसके साथ, RBL एक ही कार्ड में पेमेंट क्षमताओं की इन व्यापक सुविधाओं की पेशकश करने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है।
- इस एकीकरण से क्रेडिट कार्डधारक UPI के माध्यम से तत्काल और सुरक्षित पेमेंट करने में सक्षम होंगे और NMC सुविधाओं के साथ परेशानी मुक्त यात्रा कर सकेंगे।

**10. हाल ही में (जुलाई'24 में) किस बैंक ने सीमा पार भुगतान में होने वाले भुगतान धोखाधड़ी को रोकने में मदद करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-ड्रिवेन पायलट लॉन्च करने के लिए सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस (**SWIFT**) के साथ भागीदारी की है?**

- 1) एक्सिस बैंक
- 2) HDFC बैंक
- 3) पंजाब और सिंध बैंक
- 4) फेडरल बैंक
- 5) ICICI बैंक

उत्तर- **1)एक्सिस बैंक**

**स्पष्टीकरण:**

सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस (**SWIFT**) ने सीमा पार भुगतान में होने वाली भुगतान धोखाधड़ी को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-ड्रिवेन पायलट लॉन्च करने के लिए अग्रणी भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक (**PSB**) **एक्सिस बैंक** के साथ साझेदारी की है।

- AI-ड्रिवेन पायलट से एक सुरक्षित बुनियादी ढांचा प्रदान करने की उम्मीद है जो वित्तीय संस्थानों को मजबूत गोपनीयता-संरक्षण मॉडल के साथ महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान-प्रदान करने की अनुमति देगा।
- इस पहल में बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्पोरेशन (BNY मेलॉन) (संयुक्त राज्य अमेरिका-USA), ड्यूश बैंक AG (जर्मनी), डी नीदरलैंड्स बैंक (DNB) (नॉर्वे), HSBC होल्डिंग्स plc (यूनाइटेड किंगडम-UK), इंटेसा सैनपोलो (इटली) और स्टैंडर्ड बैंक (दक्षिण अफ्रीका) जैसे वैश्विक बैंक शामिल हैं, जो सुरक्षित डेटा सहयोग और फेडरेटेड लर्निंग टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर रहे हैं।
- पायलट ऐतिहासिक लेनदेन डेटा की जांच करने के लिए AI एल्गोरिदम का उपयोग करेगा और किसी भी प्रकार की विसंगति का पता लगाएगा जो धोखाधड़ी की ओर इशारा करती है।

**11. हाल ही में (जुलाई'24 में) किस फिनटेक कंपनी ने जुलाई 2024 में भारत का पहला नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया, जो मोबाइल QR पेमेंट के साथ NFC कार्ड पेमेंट तकनीक को एकीकृत करता है?**

- 1) भारतपे
- 2) रेजरपे
- 3) पेटीएम
- 4) PayU
- 5) PhonePe

उत्तर- **3) पेटीएम**

#### **स्पष्टीकरण:**

नोएडा स्थित (उत्तर प्रदेश, UP) One 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (OCL), पेटीएम की मूल कंपनी ने भारत का पहला नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया, जो एक टू-इन-वन मोबाइल क्लिक रिस्पॉन्स (QR) पेमेंट डिवाइस है जो NFC कार्ड पेमेंट तकनीक को मोबाइल QR पेमेंट के साथ जोड़ती है।

- पेटीएम NFC कार्ड साउंड बॉक्स ऑफलाइन व्यापारियों के लिए एक लागत प्रभावी समाधान प्रदान करेगा और ग्राहकों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड टैप करके या QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने की अनुमति देगा।
- इसमें तत्काल ऑडियो पुष्टिकरण और लेनदेन राशि के लिए एक डिस्प्ले स्क्रीन और **10 दिनों** तक चलने वाली बैटरी लाइफ की सुविधा है।
- व्यापारी NFC-बेस्ड डेबिट और क्रेडिट कार्ड स्वीकार कर सकते हैं और एक ही डिवाइस से किसी भी UPI ऐप से मोबाइल पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं।

**12. जुलाई 2024 में जारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर डायरेक्शन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विनियमित संस्थाएँ (RE) शामिल थीं?**

**A) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियाँ (NBFC) (आवास वित्त कंपनियाँ (HFC) सहित)**

**B) सहकारी बैंक (शहरी सहकारी बैंक (UCB) / राज्य सहकारी बैंक (StCB) / केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB))**

**C) वाणिज्यिक बैंक (CB) [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFI) सहित]**

- 1) केवल A & B
- 2) केवल A & C
- 3) केवल B & C
- 4) केवल B
- 5) सभी A, B & C

उत्तर- **सभी A, B & C**

#### **स्पष्टीकरण:**

15 जुलाई, 2024 को, भारतीय रिजर्व बैंक (**RBI**) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों सहित वाणिज्यिक बैंकों; शहरी, राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों; और गैर-बैंकिंग वित्त फर्मों और आवास वित्त कंपनियों जैसे विनियमित संस्थाओं (**RE**) के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर **3 मास्टर डायरेक्शन (MD)** जारी किए, जो पिछले दिशानिर्देशों को बदलने और 36 मौजूदा परिपत्रों को समेकित करने के लिए हैं।

- **उद्देश्य:** RE में धोखाधड़ी की रोकथाम, शीघ्र पता लगाने और समय पर रिपोर्ट करने के लिए एक मजबूत रूपरेखा प्रदान करना।
- निर्देशों में RE को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (**SBI**) बनाम राजेश अग्रवाल पर मार्च 2023 के सर्वोच्च न्यायालय (**SC**) के फैसले को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों/संस्थाओं को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले समयबद्ध तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है।

**RBI ने धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर MD की रिपोर्ट जारी की**

- गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियाँ (NBFC) (आवास वित्त कंपनियाँ (HFC) सहित)
- सहकारी बैंक (शहरी सहकारी बैंक (UCB) / राज्य सहकारी बैंक (StCB) / केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB))

- वाणिज्यिक बैंक (CB) [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFI) सहित] [अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें](#)

**13. भारत सरकार (GoI) और विश्व बैंक (WB) ने हाल ही में (अगस्त'24 में) ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट (GNHCP) के निर्माण के लिए एक \_\_\_\_\_ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।**

- 1) 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर
- 2) 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर
- 3) 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर
- 4) 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर
- 5) 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर

उत्तर- 2) 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर

**स्पष्टीकरण:**

1 अगस्त 2024 को, केंद्रीय मंत्री **नितिन गडकरी**, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने घोषणा की कि भारत सरकार (GoI) और विश्व बैंक (WB) ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट (GNHCP) के निर्माण के लिए **500 मिलियन अमेरिकी डॉलर** के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- इस परियोजना का उद्देश्य हरित प्रौद्योगिकियों और जलवायु लचीलापन पद्धति का उपयोग करके एक सुरक्षित और हरित राजमार्ग को तैनात करना है।
- MoRTH ने यह भी बताया कि GNHCP परियोजना के अंतिम रूप से पूरा होने की निर्धारित तिथि **मई 2026** है।
- विश्व बैंक 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान करके परियोजना का समर्थन करेगा, जो कुल परियोजना लागत **1288.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर** (जो 7,662.47 करोड़ रुपये के बराबर है) में योगदान देगा।

**14. निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में (अगस्त'24 में) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (IDBI) लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से 'फिट & प्रॉपर' प्रमाणपत्र प्राप्त किया है?**

- A) एमिरेट्स NBD बैंक
  - B) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
  - C) कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
- 1) केवल A & B
  - 2) केवल B & C
  - 3) केवल A & C
  - 4) केवल B
  - 5) सभी A, B & C

उत्तर- 3) केवल A & C

**स्पष्टीकरण:**

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (IDBI) लिमिटेड के लिए 3 संभावित दावेदारों को 'फिट & प्रॉपर' प्रमाणपत्र जारी किए हैं, जिससे बैंक के संभावित अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है।

- संभावित दावेदार फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, टोरंटो (कनाडा); एमिरेट्स NBD बैंक, दुबई (संयुक्त अरब अमीरात (UAE)) और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (KMBL), मुंबई (महाराष्ट्र) हैं।
- IDBI को निजीकरण के लिए 'फिट & प्रॉपर' मानदंड के लिए RBI से अंतिम मंजूरी मिल गई है, और रणनीतिक बिक्री के लिए संभावित बोलीदाताओं द्वारा अगस्त, 2024 की शुरुआत में उचित परिश्रम की प्रक्रिया शुरू करने की उम्मीद है।
- भारत सरकार (GoI) और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास संयुक्त रूप से IDBI बैंक में लगभग 94% हिस्सेदारी है। IDBI बैंक के प्रमोटर के रूप में LIC के पास 49.24% हिस्सेदारी है, जबकि सह-प्रवर्तक के रूप में GoI के पास IDBI बैंक में 45.48% हिस्सेदारी है।

**15. किस भारतीय फर्म ने हाल ही में (अगस्त'24 में) भारतीयों और अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए ग्लोबल इन्वेस्टिंग तक पहुँच प्रदान करने के लिए वेस्टेड फाइनेंस इंक के साथ साझेदारी की है?**

- 1) एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
- 2) एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड
- 3) ECL फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
- 4) मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- 5) HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड

**उत्तर- 5) HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड**

**स्पष्टीकरण:**

HDFC बैंक लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी **HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड** ने ग्लोबल इन्वेस्टिंग 2.0 के माध्यम से भारतीयों और अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए ग्लोबल इन्वेस्टिंग को लोकतांत्रिक बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) स्थित निवेश मंच वेस्टेड फाइनेंस इंक. के साथ साझेदारी की है।

- ग्लोबल इन्वेस्टिंग 2.0 के साथ, HDFC सिक्योरिटीज निवेशकों को उनके निवेश का विस्तार करने के लिए आवश्यक उपकरण और पहुँच प्रदान करेगी।
- यह साझेदारी निवेशकों को संवर्धित सुरक्षा, नवीन सुविधाएँ और गहन पोर्टफोलियो विविधीकरण प्रदान करेगी।
- USA विनियमों और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की उदारीकृत प्रेषण योजना का पालन, जिससे भारतीय निवासी सालाना 250,000 अमेरिकी डॉलर तक निवेश कर सकते हैं।

**16. जुलाई 2024 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 3 मर्चेंट पेमेंट कंपनियों **IndiaIdeas.com लिमिटेड** (बिलडेस्क), अमेजन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और ग्लोबल पेमेंट्स मेजर एडेन इंडिया टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एडेन) को \_\_\_\_\_ लाइसेंस दिया है।**

- 1) प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रमेंट्स (PPI)
- 2) थर्ड-पार्टी ऐप प्रोवाइडर (TPAP)
- 3) सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR)
- 4) पेमेंट-एग्रीगेटर-क्रॉस बोर्डर (PA-CB)
- 5) कॉर्पोरेट एजेंट (CR)

**उत्तर- 4) पेमेंट-एग्रीगेटर-क्रॉस बोर्डर (PA-CB)**

**स्पष्टीकरण:**

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 3 मर्चेंट पेमेंट कंपनियों **IndiaIdeas.com लिमिटेड** (बिलडेस्क), अमेजन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और ग्लोबल पेमेंट्स मेजर एडेन इंडिया टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एडेन) को पेमेंट-एग्रीगेटर-क्रॉस बोर्डर (PA-CB) लाइसेंस दिया है।

- बिलडेस्क को निर्यात और आयात (PA-CB-E&I) दोनों के लिए लाइसेंस मिला और अमेजन पे और एडेन को केवल आयात (PA-CB-I) के लिए लाइसेंस मिला।
- यह PA-CB लाइसेंस इन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू मर्चेंट पेमेंट सर्विसेज के लिए पेमेंट सर्विसेज प्रदान करने की अनुमति देता है।
- PA-CB लाइसेंस पेमेंट कंपनियों को विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण और भारत की वैश्विक कंपनियों के साथ काम करने वाले फ्रीलांसरों के लिए पेमेंट के निर्यात-आयात क्षेत्र में पेमेंट सर्विसेज प्रदान करने में सक्षम बनाता है। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

**17. एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के खराब और संदिग्ध ऋण रिजर्व (BDDR) पर संशोधित निर्देशों के अंतर्गत किस प्रकार के सहकारी बैंक आते हैं?**

- A) शहरी सहकारी बैंक
  - B) राज्य सहकारी बैंक
  - C) प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ
- 1) केवल A

- 2) केवल B
- 3) केवल A & C
- 4) केवल A & B
- 5) सभी A, B & C

उत्तर- 4) केवल A & B

#### स्पष्टीकरण:

2 अगस्त 2024 को, भारतीय रिज़र्व बैंक (**RBI**) ने विवेकपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस रिज़र्व के उपचार में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी बैंकों के लिए खराब और संदिग्ध ऋण रिज़र्व (**BDDR**) पर संशोधित निर्देश जारी किए।

- ये संशोधित निर्देश शहरी सहकारी बैंकों (UCB), राज्य सहकारी बैंकों (StCB) और केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCB) पर तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
- संशोधित निर्देश AS-अनुपालित दृष्टिकोण में सुधार और सुचारू परिवर्तन प्रदान करने की दृष्टि से एकबारगी उपाय के रूप में कार्य करेंगे।
- बैंकों को **31 मार्च, 2024** तक **BDDR** शेष राशि की पहचान करने और मात्रा निर्धारित करने का आदेश दिया गया है, जो व्यय के रूप में पहचानने के बजाय शुद्ध लाभ को विनियोजित करके बनाई गई थी।
- **31 मार्च, 2025** तक NPA के लिए प्रावधान करने के लिए विनियोग सीधे P&L खाते या सामान्य रिज़र्व से ('लाइन के नीचे') किया जाना चाहिए।

18. हाल ही में (अगस्त'24 में) कौन सा राज्य भारतीय स्टेट बैंक (**SBI**) जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करके डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सोल्युशन (**DRTPS**) को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है?

- 1) असम
- 2) नागालैंड
- 3) केरल
- 4) उत्तराखण्ड
- 5) हिमाचल प्रदेश

उत्तर- 2) नागालैंड

#### स्पष्टीकरण:

2 अगस्त 2024 को, नागालैंड सरकार ने डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सोल्युशन (**DRTPS**) के लिए भारतीय स्टेट बैंक (**SBI**) जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ, नागालैंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस सोल्युशन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

- MoU पर तत्काल प्रभाव से **3 साल** (2024 से 2027) की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे।
- DRTPS, एक पैरामीट्रिक मल्टी-ईयर रिस्क ट्रांसफर सोल्युशन नागालैंड के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में मदद करेगा और आपदा के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करेगा।
- इंश्योरेंस पूरे नागालैंड को कवर करता है और नागालैंड सरकार इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान भी करेगी। यदि कोई आपदा होती है, तो बीमाकर्ता **3 साल** तक बचाव के लिए आएगा।

19. थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए **RuPay AED** (संयुक्त अरब अमीरात दिरहम) फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है?

- 1) अमेरिकन एक्सप्रेस
- 2) मास्टरकार्ड
- 3) वीज़ा
- 4) नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

## 5) डाइनर्स क्लब

### उत्तर- 4) नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

#### स्पष्टीकरण:

मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित थॉमस क्रुक (इंडिया) लिमिटेड (TCIL) ने RuPay AED (संयुक्त अरब अमीरात दिरहम) फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के साथ साझेदारी की है, जो संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए पहला RuPay प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड है। यह कार्ड NPCI के प्रौद्योगिकी भागीदार CARD91 द्वारा संचालित है।

- यह अभिनव मेड इन इंडिया पहल एक भारतीय गैर-बैंकिंग इकाई के साथ अपनी तरह की पहली साझेदारी है।
- यात्री UAE में लेनदेन और ATM निकासी के लिए थॉमस क्रुक के RuPay (AED) कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।

### 20. हाल ही में किस संस्थान ने साइबरसिक्योरिटी लेब स्थापित करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (IDBI) के साथ साझेदारी की है?

1) IIT हैदराबाद

2) IIT खड़गपुर

3) IIT मद्रास

4) IIT कानपुर

5) IIT बॉम्बे

### उत्तर- 3) IIT मद्रास

#### स्पष्टीकरण:

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-मद्रास (IITM), चेन्नई, तमிலनाडु ने स्वास्थ्य सेवा, फिनटेक और एयरोस्पेस में सुरक्षा समाधान विकसित करने और तैनात करने के लिए IITM परिसर में 'IDBI-IITM सिक्योर सिस्टम लैब' (I2SSL) स्थापित करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (IDBI) के साथ साझेदारी की है।

i. यह अत्याधुनिक साइबरसिक्योरिटी लेबोरेटरी साइबरसिक्योरिटी, उत्पादीकरण और अनुसंधान कार्य के व्यावसायीकरण, विशेष रूप से मोबाइल टेक्नोलॉजी के बाजार के लिए तैयार IP बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है।

ii. यह प्रायोगिक मूल्यांकन और आकलन अभ्यास करेगा, परीक्षण मामले विकसित करेगा, अनुसंधान करेगा और उद्यमों को वास्तविक समय में साइबरसिक्योरिटी जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश तैयार करेगा।

### 21. किस इंश्योरेंस फर्म ने हाल ही में (अगस्त'24 में) युवा टर्म/डिजी टर्म और युवा क्रेडिट लाइफ/डिजी क्रेडिट लाइफ सहित चार नए उत्पाद लॉन्च किए हैं?

1) HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी

2) टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी

3) लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

4) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी

5) स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी

### उत्तर- 3) लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

#### स्पष्टीकरण:

5 अगस्त, 2024 को, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ने भारत के युवाओं के लिए चार नए उत्पाद लॉन्च किए, जिनमें LIC का युवा टर्म/डिजी टर्म और LIC का युवा क्रेडिट लाइफ/डिजी क्रेडिट लाइफ शामिल हैं, जो 6 अगस्त, 2024 से बिक्री के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

i. LIC का युवा टर्म प्लान ऑफलाइन उपलब्ध है। इस प्लान को लाइसेंस प्राप्त एजेंटों, कॉर्पोरेट एजेंटों, ब्रोकर और इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्मों के माध्यम से ऑफलाइन खरीदा जा सकता है। जबकि LIC का डिजी टर्म प्लान LIC की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध है। मृत्यु पर देय लाभ की गारंटी है।

- ये नॉन-पार, नॉन-लिंकड, लाइफ, इंडिविजुअल, प्योर रिस्क प्लान जवान व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो एरली टर्म इंश्योरेंस चाहते हैं, जो ऑफलाइन या ऑनलाइन खरीदने की सुविधा प्रदान करते हैं।
- ii. LIC का युवा क्रेडिट लाइफ, जो बिचौलियों के माध्यम से **ऑफलाइन** उपलब्ध, और LIC का डिजी क्रेडिट लाइफ, जो LIC की वेबसाइट के माध्यम से केवल **ऑनलाइन** उपलब्ध है, के माध्यम से **ऋण देनदारियों** को कवर करने के लिए उत्पाद पेश किए हैं।
- ये नॉन-पार, नॉन-लिंकड, लाइफ, इंडिविजुअल, प्योर रिस्क प्लान हैं, जहाँ पॉलिसी टर्म के दौरान मृत्यु लाभ कम हो जाता है।

**22. अगस्त 2024 में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने \_\_\_\_\_ को बैंकों द्वारा जारी किए गए अतिरिक्त टियर-1 (AT-1) बॉन्ड में अपने निवेश का मूल्यांकन यील्ड-टू-कॉल (YTC) के आधार पर करने का निर्देश दिया है।**

- 1) पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS)
- 2) म्यूचुअल फंड (MF)
- 3) फारैन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPI)
- 4) अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIF)
- 5) सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE)

उत्तर- 2) म्यूचुअल फंड (MF)

**स्पष्टीकरण:**

5 अगस्त 2024 को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड (MF) को यील्ड-टू-कॉल (YTC) आधार पर बैंकों द्वारा जारी किए गए अतिरिक्त टियर-1 (AT-1) बॉन्ड में अपने निवेश का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है।

- यह निर्देश राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) द्वारा [रिपोर्ट ऑन वैल्यूएशन मेथडोलॉजी ऑफ AT-1 बॉन्ड्स](#) आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), वित्त मंत्रालय (MoF) को सौंपे जाने के बाद आया है, जिसमें सिफारिश की गई है कि AT-1 बॉन्ड का मूल्यांकन YTC के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि बाजार प्रथाओं और Ind AS (भारतीय लेखा मानक) 113 सिद्धांतों के साथ संरेखित किया जा सके।
- **AT-1 बॉन्ड:** इन बॉन्ड को स्थायी ऋण साधन के रूप में भी जाना जाता है जो बैंकों द्वारा धन जुटाने और अपनी मुख्य इकिटी पूँजी बनाने के लिए जारी किए जाते हैं।
- **यील्ड-टू-कॉल (YTC):** यह अपेक्षित रिटर्न है जो बॉन्ड धारक या निवेशक को मिलेगा, यदि बॉन्ड को कॉल तिथि तक रखा जाता है, जो बॉन्ड के परिपक्तता तक पहुंचने से कुछ समय पहले होगा।

**23. किस बैंक ने हाल ही में (अगस्त'24 में) चालू वित्त वर्ष 2024-25 में टियर-1 और टियर-2 बॉन्ड जारी करके 25,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है?**

- 1) HDFC बैंक
- 2) ICICI बैंक
- 3) एक्सिस बैंक
- 4) पंजाब नेशनल बैंक
- 5) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

उत्तर- 5) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

**स्पष्टीकरण:**

3 अगस्त 2024 को, भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)- मुंबई (महाराष्ट्र) के केंद्रीय बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में **टियर-1** और **टियर-2** बॉन्ड जारी करके **25,000 करोड़ रुपये** तक धन जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

- i. धन भारतीय रुपये (INR) या यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर (USD) में जुटाया जाएगा और बॉन्ड बेसल-III के अनुरूप होंगे, जो भारत सरकार (GoI) की मंजूरी के अधीन है, जहाँ भी आवश्यक हो।
- ii. यह घोषणा SBI द्वारा FY25 के लिए अपने Q1 (अप्रैल-जून) परिणामों के साथ की गई थी।

**24. हाल ही में (अगस्त'24 में) किस बैंक ने उन किसानों को सशक्त बनाने के लिए "किसान का सम्मान" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिन्होंने बैंक के साथ अपने लेन-देन में असाधारण वित्तीय अनुशासन और तत्परता का प्रदर्शन किया है?**

1) जम्मू & कश्मीर बैंक

2) RBL बैंक

3) कर्नाटक बैंक

4) फेडरल बैंक

5) तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक

उत्तर- **1) जम्मू & कश्मीर (J&K) बैंक**

**स्पष्टीकरण:**

1 अगस्त 2024 को, जम्मू और कश्मीर (**J&K बैंक**) ने J&K के उन किसानों को सशक्त बनाने के लिए "किसान का सम्मान" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया, जिन्होंने बैंक के साथ अपने लेन-देन में असाधारण वित्तीय अनुशासन और तत्परता का प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम **30 सितंबर, 2024** तक चलेगा।

- कार्यक्रम का शुभारंभ J&K बैंक के प्रबंध निदेशक (**MD**) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (**CEO**) बलदेव प्रकाश ने J&K बैंक के कार्यकारी निदेशक (**ED**) सुधीर गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्रीनगर, J&K में किया।
- कार्यक्रम उन किसानों की पहचान करेगा जिन्होंने लगातार अपने किसान क्रेडिट कार्ड (**KCC**) का नवीनीकरण किया है और वित्तीय अनुशासन दिखाया है।
- पहचान किए गए** किसानों को विभिन्न शाखाओं, समूहों और क्षेत्रीय स्तरों पर 'प्रशंसा प्रमाण पत्र (**CoA**)' से सम्मानित किया जाएगा।

**25. निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान ने हाल ही में (अगस्त'24 में) फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड (FPEL) में 275 मिलियन अमेरिकी डालर के निवेश की घोषणा की है?**

A) इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IFC)

B) एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB)

C) DEG (Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH)

1) केवल A & B

2) केवल A & C

3) केवल B & C

4) केवल A

5) सभी A, B & C

उत्तर- **5) सभी A, B & C**

**स्पष्टीकरण:**

6 अगस्त, 2024 को हैदराबाद, तेलंगाना स्थित अक्षय ऊर्जा कंपनी फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड (FPEL) को इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IFC), एशियन डेवलपमेंट बैंक (**ADB**) और **DEG**(Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH) सहित तीन विकास वित्तीय संस्थानों (DFI) के एक संघ से **275 मिलियन अमेरिकी डॉलर** (लगभग 2280 करोड़ रुपये) का निवेश प्राप्त हुआ है।

- विश्व बैंक (WB) समूह का IFC, वाशिंगटन, DC, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) **125 मिलियन अमेरिकी डॉलर** का निवेश कर रहा है, फिलीपींस स्थित ADB 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान कर रहा है, और जर्मनी का निवेश निगम, DEG 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है।
- ADB के योगदान में दो भाग: इसके साधारण पूँजी संसाधनों से **70 मिलियन अमेरिकी डॉलर** और इसके अग्रणी एशिया के निजी क्षेत्र अवसंरचना कोष 2 (LEAP 2) से **30 मिलियन अमेरिकी डॉलर** शामिल हैं।
- यह पूँजी निवेश **2026** तक अपने अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो को **3.5 गीगा वाट (GW)** तक विस्तारित करने के FPEL के लक्ष्य का समर्थन करेगा।